www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित — हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 02 | गोरखपुर, 14 जुलाई 2024 रविवार | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2

कश्मीर पर बहुतों की निगाह रही है

सुप्रीम कोर्ट ने जहां केन्द्र सरकार को सितम्बर से पहले चुनाव कराने के लिए कहा था वहीं केनद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी यह कहा था कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करायेंगे ।किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली करके ही वहां की जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयत्र किया जा सकता है।जिस प्रकार से आतंकी घटनाएं सज्य में घट रही हैं और कश्मीर घाटी के बजाय उस-।का केन्द्र जम्मू के आस-पास का क्षेत्र बन गया है।इससे यही लगता हैं कि आतंकियों की रणनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आया है जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं।आखिर ये आतंकी आ कहां से रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं।यदि सेना और सुरक्षाबल जो 1989 से आतंकियों का सफाया कर रहे हैं।अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह खत्म होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है तो यह रक्तबीज कहां से पैदा हो रहे हैं।इस पर भी एक बार सोचना ही पड़ेगा ? हम कब तक अपने जवानों की शहादत देते रहेंगे?

जम्मू कश्भीर में आतंकवादी गतिविधियां धमने का नाम नहीं ले रही है।कुआ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में पांच जवानों की शहादत हो गई।इस समय आतंकवाद का केन्द्र दरक्षिण कश्मीर के बजाय जम्मू का इलाका हो गया है जहां कई घटनाएं घट चुकी हैं। कठुआ में हुए आतंकियों के एक हमले में हमारे सेना के पांच जवान शहीद हो गए हैं जो सभी उत्तराखंड के थे जिनके पार्थि शरीर को राष्ट्र्य सम्मान के साथ अन्तिम विदाई दी गई ।

जम्मू कश्मीर 1989 से आतंकवाद से जुझ रहा है।इस दौरान अनगिनत नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़डा और सेना और सुरक्षाबलों की कार्रवाइयों में अनगिनत आातंकवादियों का सफाया किया गया।जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त केन्द्र सरकार द्वारा यह दावा किया गया था इससे वहं आतंकवाद समाप्त हो जायेगा।आतंकवाद की रीढ़ टूट जायेगी।कश्मीर के तीन परिवारों ने कश्मीर को लूटा है आदि-आदि। जम्मू कश्मीर के अधिकाश नेताओं को जेलों में भेज दिया गया था।इंटरनेट व अन्य सम्पर्क के साधन असे तक बंद थे।लोग एक तरह से जेलों में रह रहे थे।मस्जिदों में नमाज बंद करा दी गई थी।कश्मीर एक बंद जेल का हिस्सा बन गया था। वहां की विधानसभा समाप्त करके उसे केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया।अब चुनाव की सुगबुगाहट है।केन्द्रीय चुनाव आयोग ने वहां जल्द चुनाव कराने का वास्ता दिया है। वहां राजनीतिक प्रक्रिया ठहरी हुई है। राज्यपाल स्वयं आरोपों के घेरे में हैं।नौकरशाही का पुरा राज है।अभी हाल ही में योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कश्मीर में जाकर वहां की महिलाओं के साथ सेल्फी की फोटो लेकर यह सन्देश देने की कोशिश की थी कि अब कश्मीर में सब कुछ सामान्य है।अनुच्छेद 370 के हटने पर जम्मू और लद्दाख ने सबसे अधिक खुशियां मनायी थीं उनके लिए वह आजादी जैसा दिन था लगता था कि अभी तक सारा लाभ श्रीनगर और घाटी के इलाके को मिल जाता था और वह लोग उपेक्षित हो जाते हैं लेकिन अब तो श्रीनगर और घाटी की कौन कहे जम्मू और लद्दाख को भी लग रहा है कि वह छले गए हैं जो सपने उन्हें दिखाए गए थे वह अस्तित्व में ही नहीं हैं।5 अगस्त 2019 की मोदी सरकार ने जम्म कश्मीर को दो भागों में बांट दिया लद्दाख को बिना नुमाइदे के कर दिया और जम्म कश्मीर के लिए जो विधानसभा होनी थी उसके अभी तक चुनाव ही नहीं हाए हैं।अनुच्छेद 370 हटाये हाए पांच साल होने को हैं तब से यह तो नहीं कहा जा सकता है कि हालात सुधर गाए है। वहा अब ता हर तरह क हलात खराव है।आए दिन मुठभेड होती है हर बार कहा जाता है हमने आत्तकियों का सफाया कर दिया लेकिन उसके बाद खबर आती है हमारे जवान भी शहीद हो गाए। आखिर यह सिलसिला क्या अंतहीन है? जम्मू कश्मीर पर हमारी नीति यदि डंडे के बल पर जनता को हांकने की ही रहेगी तो उससे स्थितियां कभी नहीं सुधरेंगी।कश्मीर पर बहतों की निगाह रही है आजादी के बाद भी यह भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था।जब देश आजाद होकर दो भागों में हो गया था तब भी कश्मीर न भारत के पास था न ही पाकिस्तान के पास।उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि महाराजा हरी सिंह उसे एक स्वतंत्र राज्य बनाये रखने के पक्षधर थे जिसके कारण उन्होंने न तो भारत में विलय किया और न ही पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंडस्टिल समझौता जरूर कर लिया था जिसमें डाक, तार रसद और रक्षा जैसी स्थतियों को पाकिस्तान के जिम्मे कर दिया था लेकिन इसका क्या हश्र हुआ यह अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। अंततः अपना राज्य जाते देख उन्हें भारत के साथ आना पड़ा क्योकि भारत किस आधार पर उनके राज्य की सुरक्षा करता?

सरकार ने परिसीमन कराकर यह जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास किया कि घाटी के इलाके में अधिक सीटें न जायें जिससे जम्मू निर्णायक हो जाए लेकिन आज तक क्या हआ? चुनाव कराने तक की स्थिति नहीं बन पाई है।नौकरशाहों कीबल्ले-बल्ले अवश्य है।जो अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होते थे उसे जीकरशाह भोग रहे हैं अनुच्छद 370पर अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग् चुकी है लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अब पछता रहे हैं।उनकी खुशियां काफूर हो चुकी हैं।उनका न तो कोई नुमाइंदा है और न ही खैरख्वाह। लहाख में लम्बे समय से आंदोलनरत सोनम वांगचुक अपने लए तो कुछ नहीं मांग रहे थे। वह लद्दाख के पर्यावरण और उसकी सार्मरिक स्थित् को देखते हए कन्द्र से अनुरोध कर रहे थे लेकिन उनकी किसी ने नहीं सनी कश्मीर की दो ऐसी लोकसभा सीटें भी रहीं जहां उमर अबद्रद्य और महबूबा मुफ्ती तक लंबे अन्तर से हार गई।अपनी हार देखते हाए वह गिनती छोडर चली गाई और एक्स पर ट्वीट किया लेकिन जीता कौन? यह ती अव आप भी जान गए हैं, जो जेल में थे जिन पर आतंकी होने का आरोप है।पंजाब में भी ऐसे दो निर्दलीय जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं जिन्हें शपथ लेने के लिए अदालत को दिशेष अनुमति दी।

संविधान के आस्थावान ही संविधान की रक्षा करेंगे : प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग संविधान हत्या दिवस मनाएंगे।

केंद्र ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाना हमें याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था। प्रियंका ने एक्स पर एक पोस्ट में उल्लेख किया हैकि भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आजादी और अपना संविधान हासिल किया है।जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वे ही संविधान की रक्षा करेंगे।

बसपा नेता हत्याकांड के आरोपी को चेन्नई में पुलिस ने मार गिराया

चेन्नई। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के. आर्मस्ट्रांग की हत्या के एक प्रमुख आरोपी ने रविवार को यहां पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और हिरासत से भागने की कोशिश की, जिस दौरान उसे मार गिराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जब आरोपी के. थिरुवेंगदम को जांच के तहत उत्तरी चेन्नई के एक स्थान पर ले जाया गया, तो उसने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसपर गोली चलाई। थिरूवेंगदम को बसपा नेता की हत्या में इस्तेमाल किये जाने के बाद छिपाकर रखे गये हथियारों की तलाश करने के लिए वहां ले जाया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थिरुवेंगदम (30), बसपा नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में गिरफ्तार किये गए 11 आरोपियों में से एक था और वह एक कुख्यात अपराधी था। यहां की एक अदालत ने कुछ ही दिन पहले सभी आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आर्मस्ट्रांग की यहां पांच जुलाई को एक गिरोह ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया था।

पुलिस और सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया था।पुलिस ने 11 जुलाई को पुदुकोट्टई जिले में एक कुख्यात अपराधी को भी मार गिराया था।

खूंटी में जमीन विवाद को लेकर दंपती की हत्या

रांची। झारखंड के खूंटी जिले में जमीन विवाद को लेकर एक दंपती की उनके ही परिवार के एक सदस्य ने कथित तौर पर हत्या कर दी।पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना शुक्रवार शाम को रनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत झोरा टोली गांव में घटी। तोरपा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने कहा कि सुकरा मल्लाह अपने आंगन में चिकन पका रहा था, तभी उसके चचेरे भाई लूटो मल्लाह ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लूटो ने सुकरा पर कथित तौर पर एक धारदार हथियार से भी हमला किया, जिससे वह (सुकरा) गंभीर रूप से जख्मी हो गया और दम तोड़ दिया। केरकेट्टा ने कहा, जब सुकरा की पत्नी उसे बचाने के लिए आगे आई तो उसने उसकी भी हत्या कर दी।लूटो को रोकने की कोशिश में सुकरा की मां और बेटा भी घायल हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को संदेह है कि यह घटना जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद के चलते हुई है।

पंजाब में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने त्रिकोणीय मुकाबले में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र हासिल कर लिया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने विक्रवंडी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित कर लिया। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई।

विपक्ष पुन: सत्तारूढ़ दल (एनडीए) को चुनौती देने की मुद्रा में

पंजाब में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने त्रिकोणीय मुकाबले में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र हासिल कर लिया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने विक्रवंडी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित कर लिया। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई।

विपक्षी इंडिया गुट उन 13 सीटों में से दस सीटें जीतकर सत्तारूढ़ एनडीए को एक बार फिर कड़ी चुनौती देता नजर आया। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से पीछे रोक देने वाली विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस ने एक बार फिर उसे 2 सीटों पर ही उपचुनाव में समेट दिया।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल उपचुनाव में एक बार फिर अपना दमदार प्रदर्श दिखाते हुए प्रदेश की सभी चार सीटें जीत लीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने तीन में से दो सीटें जीत लीं, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा में बड़ी प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरीं। उत्तराखंड में कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। पंजाब में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने त्रिकोणीय मुकाबले में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र हासिल कर लिया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने विक्रवंडी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित कर लिया।

पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई।

पंजाब- पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आप के मोहिंदर भगत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर को 37,325 वोटों से हराया। आप विधायक शीतल अंगुराल के भाजपा में शामिल होने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा की गई थी। हिमाचल प्रदेश के अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सभी तीन सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा में जीत की बधाई दी। ठाकुर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 मतों के अंतर से हराया।

हिमाचल प्रदेश- नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को 8,990 वोटों से हराया। हमीरपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को 1,571 मतों के अंतर से हराया। भाजपा के तीनों उम्मीदवार स्वतंत्र विधायक थे, जिन्होंने इस साल की शुरूआत में राज्यसभा चुनाव में भगवा पार्टी को वोट देने के बाद हिमाचल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में जहां चार सीटों पर कब्जा है, तृणमूल कांग्रेस की मधुपूर्णा ठाकुर, मुकुट मणि अधिकारी, कृष्णा कल्याणी और सुप्ति पांडे ने क्रमशः बगदा, राणाघाट, रायगंज और मानिकतला में भारी जीत हासिल की।

तृणमूल की राज्यसभा सांसद ममताबाला ठाकुर की बेटी मधुपर्णा (25) बंगाल विधानसभा की सबसे कम उम्र की सदस्य बनने जा रही हैं।

उत्तराखंड - उत्तराखंड के मंगलौर में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने भाजपा उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना को 422 वोटों के अंतर से हराया। मतदान के दिन इस निर्वाचन क्षेत्र में हिंसा देखी गई थी। बद्रीनाथ में कांग्रेस के नवागंतुक लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा के राजेंद्र भंडारी को 5,224 मतों के अंतर से हराया।

तमिलनाडु- सत्तारूढ़ द्रमुक के उम्मीदवार अन्नियुर शिवा (उर्फ शिवशानमुगम ए) ने तमिलनाडु में विक्रवंडी विधानसभा क्षेत्र में 1,24,053 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने सी अंबुमणि और नाम तमिलर काची के के अबिनया को हराया।

बिहार- बिहार में रूपौली उपचुनाव में जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल को निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 8,246 मतों के अंतर से हराया। मौजूदा विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया था, जिन्होंने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जद (यू) छोड़ दिया था।

मध्य प्रदेश - मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में, भाजपा के कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस के धीरन शाह इनवाती को 3,027 वोटों के अंतर से हराया। तीन बार के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के मार्च में भाजपा में चले जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। नतीजे पर करीबी नजर है, क्योंकि हाल तक छिंदवाड़ा को वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल नाथ का गढ़ माना जाता था।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्णकालिक बजट माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय संसद में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के लगभग समस्त देशों में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। परंतु, हाल ही के वर्षों में पूंजीवादी नीतियों के अनुसरण के कारण, विशेष रूप से विकसित देशों को, आर्थिक क्षेत्र में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह देश इन समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नियंत्रण से बाहर होती मुद्रा स्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं एवं इन देशों का सामाजिक तानाबाना भी छिनभिन्न हो गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवाद हावी रहता है अतः स्थानीय समाज में विभिन्न परिवारों के बीच आपसी रिश्ते केवल आर्थिक कारणों के चलते ही टिक पाते हैं अन्यथा शायद विभिन्न परिवार एक दूसरे से रिश्तों को आगे बढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कई विकसित देशों में तो पति-पत्नि के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। अमेरिका में तो यहां तक कहा जाता है कि 60 प्रतिशत बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है एवं केवल माता को ही अपने बच्चे का लालन-पालन करना होता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है एवं यह बच्चे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में हिंसा की दर बढ़ रही है तथा वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों के नागरिक अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं एवं उन्हें उम्मीद है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का हल भारतीय सनातन संस्कृति में से ही निकलेगा। अतः इन देशों के नागरिक अब भारतीय सनातन संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। भारत में वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद्द तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंडकाल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना रहे थे, ने भी पूं-जीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है।

भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय घाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक तानाबाना छिनभिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे।

प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तमंत्री महोदय को भी देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे मुद्रा स्फीति तो कम होगी ही परंतु साथ ही अर्थव्यवस्था में विकास की दर भी और तेज होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ते रहने से विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। परंतु यदि वस्तुओं की मांग में कमी करते हुए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास होंगे तो उत्पादों की मांग में कमी होने के चलते उत्पादों का निर्माण कम होने लगेगा, विनिर्माण इकाईयों में गतिविधियां कम होंगी एवं देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। मांग में कमी करने के प्रयास सम्बंधी सोच ही अमानवीय है। इसी प्रकार, प्राचीन भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे, इन कृषि उत्पादों के साथ ही इन कुटीर एवं लघु उद्योगों में निर्मित उत्पाद भी बेचे जाते थे। अतः ग्रामीण इलाकों से शहरों की पलायन नहीं होता था तथा नागरिकों को रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध हो जाते थे। आज की परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो सकें।

जनता पर करों के बोझ को कम करने के सम्बंध में भी विचार होना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कर सम्बंधी नीति का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को जनता पर करों का बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है। अर्थात, जनता को करों का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने बजट में भी आवश्यक वस्तुओं पर लागू करों की दरों को कम करने के प्रयास होने चाहिए। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों को भी करों में छूट देकर कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी उत्पादों को खरीदने के क्षमता बढ़े। इससे अंततः अर्थव्यवस्था को ही लाभ होता है। मध्यमवर्गीय परिवारों की खरीद की क्षमता बढ़ने से विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का चक्र और अधिक तेजी से घूमने लगता है। यदि किसी देश में अधिक से अधिक आर्थिक व्यवहार औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र भी तेज गति से घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में करों के संग्रहण में भी वृद्धि दर्ज होती है। अतः कई बार करों की दरों में कमी किए जाने के बावजूद कर संग्रहण अधिक राशि का होने लगता है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि माननीया वित्त मंत्री जी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के रूप में एक अच्छा मौका है कि भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप आर्थिक नीतियों को लागू कर पूरे विश्व को पूर्व में अति सफल रहे भारतीय आर्थिक दर्शन के सम्बंध में संदेश दिया जा सकता है।

महबूबा मुफ्ती हुई घर में नजरबंद

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें कश्मीर शहीद दिवस पर मजार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने आवास के गेट पर ताला लगे होने की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कहा कि मुझे मजार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए मेरे घर के दरवाजे एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं - सत्तावाद, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कश्मीर के प्रतिरोध और लचीलेपन का एक स्थायी प्रतीक। हमारे शहीदों का बलिदान एक वसीयतनामा है कि की भावना कश्मीरियों को कुचला नहीं जा सकता। मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज इस दिन शहीद हुए प्रदर्शनकारियों की याद में इसे मनाना भी अपराध घोषित कर दिया गया है। श्रीनगर में उन 22 प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिन्हें 1931 में तत्कालीन महाराजा की सेना ने गोली मार दी थी। केंद्र पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी सामूहिक यादों में से प्रत्येक को मिटाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को खंडित कर दिया गया, शक्तिहीन कर दिया गया और वह सब कुछ छीन लिया गया जो हमारे लिए पवित्र था। इस तरह के हमले केवल हमारे अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखने के हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत करेंगे।

टमाटर, आलू और प्याज की आसमान छूती कीमतों से कब मिलेगी राहत

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अत्यधिक गर्मी और उसके बाद अत्यधिक बारिश से दिल्ली और अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की आपूर्ति बाधित हुई। इस व्यवधान के कारण प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

नई दिल्ली। आम आदमी के लिए कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि दिल्ली और अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की खुदरा कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अत्यधिक गर्मी और भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं की लागत बढ़ गई है। शनिवार को दिल्ली में टमाटर की कीमतें 77 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं, जो एक साल पहले 168 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रभाग के आंकड़ों के अनुसार, 13 जुलाई को महाराष्ट्र में कीमतें 72.47 रुपये प्रति किलोग्राम थीं, जबकि पश्चिम बंगाल में खुदरा कीमत 71.35 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

एनसीआर में, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिले शामिल हैं, इन राज्यों में टमाटर की खुदरा कीमतें 74.64 रुपये प्रति किलोग्राम और 54.67 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। 13 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 69.31 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले साल के 114.72 रुपये प्रति किलोग्राम से काफी कम है। इन सब के बीच सरकार ने सब्सिडी वाले टमाटरों को दोबारा शुरू न करने का फैसला किया है, यह अनुमान लगाते हुए कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आपूर्ति में सुधार होने पर कीमतें एक से दो सप्ताह के भीतर स्थिर हो जाएंगी। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतें, जो बढ़कर ₹75 प्रति किलोग्राम हो गई थीं, दक्षिणी राज्यों से बेहतर आपूर्ति के साथ जल्द ही कम होने की उम्मीद है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अत्यधिक गर्मी और उसके बाद अत्यधिक बारिश से दिल्ली और अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की आपूर्ति बाधित हुई। इस व्यवधान के कारण प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान में, दिल्ली को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से टमाटर की आपूर्ति मिल रही है। अधिकारी ने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से हाइब्रिड टमाटर राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने के साथ ही कीमतें कम होने लगेंगी। यदि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण आगे कोई व्यवधान नहीं होता है तो सरकार आने वाले हफ्तों में मूल्य स्थिरीकरण के बारे में आशावादी बनी हुई है। भारी बारिश के कारण प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में टमाटर, आलू, प्याज और हरी सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे मेट्रो शहरों में कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली में 12 जुलाई को आलू की खुदरा कीमतें ₹40 प्रति किलो थीं, जो पिछले साल ₹25 प्रति किलो थी। इसी अवधि के दौरान प्याज की कीमतें ₹33 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹57 प्रति किलोग्राम हो गईं। अधिकारी ने बताया कि भारत में 283 लाख टन आलू भंडारित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन के बावजूद घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतें कम हो गई हैं और सितंबर में नई फसल के आगमन के साथ इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है। अधिकारी ने विश्वास जताया कि बाजार में ताजा आपूर्ति आने से प्याज की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। सब्जियों की कीमतों में उछाल का कारण मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले मौसम संबंधी व्यवधानों को माना गया है। हालांकि, बेहतर मौसम की स्थिति और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से आपूर्ति में वृद्धि के साथ, अधिकारियों को जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद है।

मसूद पेजेश्कियान से ईरान की जनता की उम्मीदें

पेजेश्कियान को हिजाब विरोधी माना जाता है। लंबे समय से यहां के लोगजाब का विरोध कर रहे हैं। वहां कई ऐसे सख्त नियमों का लोग सामना कर रहे हैं जिनसे कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। यहां तक कि ईरान की कुछ महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे देशों का भी रुख करने लगी हैं। ईरान की दंड संहिता, जो 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद लागू की गई थी, के मुताबिक हिजाब के बिना सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना बुरके के सार्वजनिक स्थलों पर जाना अपराध माना जाता है जिसके लिए जुर्माना या 10 दिन से दो महीने तक की कै द की सजा सुनाई जाती है। पिछले 45 वर्षों से ईरान में महिला अधिकारों की वकालत करने वाले लोग हिजाब कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। पेजस्कियान के आने के बाद लोगों में बुरके को लेकर कुछ उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन शायद कुद लोग यह बात जानते होंगे कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक नेतृत्व और सरकार के बीच विभाजित है, जिसमें राष्ट्रपति की बजाय सर्वोच्च नेता सभी प्रमुख नीतियों पर अंतिम निर्णय लेते हैं।

1954 में पैदा हुए मसूद पेजेश्कियान की मां कुर्द थीं। वे ईरान के वेस्ट अजरबाइजान प्रोविंस में पैदा हुए। 1994 में उनकी जिन्दगी का सबसे बुरा दौर आया जब एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और एक बेटी का निधन हो गया था। परिवार के दबाव के बावजूद उनहोंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। मसूद ने खुद अपने बच्चों की परवरिश अकेले की है। पेजेश्कियान ने पत्नी की मौत के 3 साल बाद ही राजनीति में कदम रखा। वे ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी के कार्यकाल में हेल्थ मिनिस्टर बने। पेजेश्कियान पर खतामी के विचारों का काफी असर है। खतामी ने भी अपनी पहचान ईरान के एक सुधारवादी नेता के रूप में बनाई थी। खतामी ने अपने कार्यकाल में ही विवादित लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी इरान के फतवे को भी खत्म किया था। हालांकि 2019 में खामेनई ने उस फतेवे को फिर से बहाल कर दिया था। पेजेश्कियान पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के काफी करीबी हैं। हिजाब का वो हमेशा से विरोध करते आए हैं। पेजेश्कियान पसंद से हिजाब पहनने के खिलाफ नहीं हैं। वो जबरन अपने विचार दूसरों पर थोपने के खिलाफ हैं। उससे भी ज्यादा उन सख्त कानूनों के खिलाफ हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, और आम नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका मानना है कि किसी को मोरल पुलिसिंग का हक नहीं है।

कहते हैं कि चर्चे आम हों तो किस्से जरूर होते हैं, इन दिनों ईरान के भी चर्चे आम हो गए हैं। नया राष्ट्रपति बनने के बाद से वहां कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्लामिक गणराज्य में किन-किन कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं। 19 मई, 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेली काप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जिसके बाद ईरान के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव तय समय सीमा से पहले कराए गए। हादसे के बाद ईरान में राजनीतिक उथल-पुथल का जो माहौल बना था वो ईरान के सुधारवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेश्कियान के देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद थम गया। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराकर नई इबादत लिखी है। ईरान में पेजेश्कियान अपने विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पेजेस्कियान ने विश्व के लिए ईरान का दरवाजा खोलने और कई इस्लामिक प्रतिबंध हटाने तथा अर्थव्यवस्था मे ंसुधार के लिए पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौता करने का वादा किया था।

ईरान मे ंसाल 2022 में महसा अमिनी को सही तरीके से हिजाब न पहनने के चलते मोरल पुलिसि ने जेल में डाल दिया था जिसके बाद अमिनी की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। महसा मौत के बाद पूरे देश में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और लोगों में बदलाव की मांग ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि वे विरोध प्रदर्शन काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ ईरानी महिलाओं द्वारा हिजाब के बिना सड़कों पर उतरने का विकल्प सरकार के लिए एक नई चुनौती है। महसा की पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु के बाद पेजेश्कियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाते हुए एक साक्षात्कार में कहा था, यह हमारी गलती है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिये सभी पर थोपना चाहते हैं।

पेजेश्कियान ने कहा था कि देश में जो भी हो रहा है, उसके लिए मेरे साथ-साथ धार्मिक विद्वान और मस्जिदें सब जिम्मेदार हैं। वर्ष 2022 में उनहोने ईरानी औरतों की आजारी के गाने औरत, जिन्दगी, आजादी को अपनी रैली में इस्तेमाल किया था। यह गाना ईरान में औरतों की आजादी के लिए चलाए गए एक अभियान का हिस्सा था। पेजेश्कियान ने अपने अभियान का नाम 'बराए ईरान' यानी ईरान के लिए रखा था। विशेषज्ञों का मानना है कि वे सुप्रीम लीडर खमनेई की मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। पेजेश्कियान को सत्ता ऐसे वक्त मिली है जब मिडिल ईस्ट में जंग जारी है।

मसूद पेजेश्कियान के राष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज होने के बाद सबकी निगाहें इसी तरफ हैं कि लगातार सख्त हिजाब कानून का विरोध करने वाले पेजेश्कियान हिजाब कानून को कितना बदल पाएंगे। क्या पिछले 45 वर्षों में ईरान में हिजाब कानून को लेकर हो रहा विराध थमेगा और हिजाब कानून में बदलाव आएगा? क्यूंकि यह तुरन्त खत्म कर देना आसान नहीं होगा। यहां के लोगो को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है जो वाकई चिंताजनक बात है। जिसमें बदलाव जरूरी है, ताकि वहां की महिलाओं में तालीम के साथ साथ रोजगार में भी इजाफा हो सके।

मुनीर नियाजी का एक शेर है-
जुर्म आदम ने किया और
नस्ल-ए-आदम को सजा
काटता हूं जिंदगी भर
मैंने जो बोया नहीं।

ईरान की आवाम भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है, जो जुर्म उन्होंने किया नहीं, उसकी सजा उन्हें मिल रही है कुछ कट्टरपंथी फतवों और सख्त कानूनों की वजह से मानों वहां आबोहवा में गलत धर्म नीतियों का जहर घुल गया है। धर्म की बातों को मानना गलत नहीं है, लेकिन उसके आधार पर गलत राजनीति करना दूसरों को नुकसान पहुंचाना यह इस्लाम नहीं कहता।

ताजिये का जुलूस

बस्ती (जीकेबी)। मोहर्रम के मद्देनजर बुधवार रात गांधीनगर में ताजिये का जुलूस निकाला गया। डीजे पर नौहा व सलाम की सदाएं जुलूस के दौरान गूंजतीं रहीं। युवाओं ने कई तरह के करतब दिखाकर युद्ध के माहौल को जीवंत करने का प्रयास किया।

जल सखियों ने लगाया शोषण का आरोप, हंगामा

बस्ती (जीकेबी)। कुदरहा ब्लॉक सभागार में जल जीवन मिशन के तहत जल सखियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होते ही सखियों ने शोषण का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सखियों ने बताया कि सुबह से ही प्रशिक्षण के नाम पर बुला लिया गया और चाय-पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई।

आरोप लगाया कि उमस भरी गर्मी में पंखे तक का इंतजाम नहीं किया गया। दो साल बीत जाने के बाद किसी जल साखी को जांच किट नहीं दी गई। जल सखी नीलम मिश्रा, मीरा गोस्वामी, शर्मिला, रिंकी, संगीता, पूजा, नीलम सुभांगी, अंजू कुमारी आदि ने बताया कि आवेदन के समय जल सखियों को छह हजार रुपये माह मानदेय देने की बात कही गई थी। मगर, अब प्रति जांच पर 20 रुपये देने की बात बताई जा रही है। प्रशिक्षक दुर्गेश कुमार दुबे ने बताया कि जल सखियों को जांच किट उपलब्ध करा दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे ने बताया कि जल सखियों की शिकायत पर दोबारा प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ आलोक कुमार पंकज ने बताया कि कुछ दिक्कतें आई थीं। निस्तारित कर ली गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है।

▸ नेपाल में बारिश के आगे गोरखपुर-बस्ती मंडल बेबस-

राप्ती और गंडक खतरे के निशान से ऊपर

गोरखपुर(जीकेबी)। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिले के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के छह गांवों बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गंडक खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके चलते महराजगंज और कुशीनगर में नदी के किनारे बसे गांवों की हजारों एकड़ खेती डूब गई है।

सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते संतकबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिले के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के छह गांवों बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गंडक खतरे के निशान को पार कर गई है।

इसके चलते महराजगंज और कुशीनगर में नदी के किनारे बसे गांवों की हजारों एकड़ खेती डूब गई है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते संतकबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

गोरखपुर मंडल की प्रमुख नदियां गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, सरयू और रोहिन हिमालय से निकली हैं। नेपाल के तराई वाले क्षेत्र से ये नदियां यूपी में प्रवेश करती हैं। इसमें से गंडक नदी पर वाल्मीकिनगर में बैराज बना है, जबकि अन्य नदियों में पानी सीधे सैलाब लाता है। नेपाल के पहाड़ों पर जब भी बारिश होती है तो ढलान के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है।

वाल्मीकिनगर बैराज में पानी बढ़ने पर एक बार में ही हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। शुक्रवार को गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बैराज से 3 लाख 30 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी खतरे के निशान से 28 सेमी ऊपर बह रही है, जिसके चलते महराजगंज के अलावा कुशीनगर में भी करीब 30 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां मवन नाले का जलस्तर बढ़ने के चलते कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास तक पानी पहुंच गया है। इसी तरह महराजगंज में जिले में चंदन, झरही उर्फ प्यास और भौरहियां नाले का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खैरी उर्फ झुंगहवा, तौलिहवा, खैरी शीतल प्रसाद, मटियार उर्फ भुतहवा आदि गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। हर साल इन गांवों के लिए बरसात में दिक्कत बढ़ जाती है। खेती भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

माना जा रहा है कि इस साल धान की खेती में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संतकबीरनगर जिले में भी सरयू का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। जिले के धनघटा तहसील क्षेत्र के गायघाट दक्षिणी, सियरकला, दौलतपुर, गुनवतिया, चकदहा, सुअरहा, भौवापार आदि गांव के चारों तरफ पानी पहुंच गया है। लोग बांधों पर सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं।

सरकार बदलने के बाद भारत के संबंधों पर चर्चा शुरू

प्रतीत होता है कि ईरान भी चीन के साथ अपने संबंध पहले से और ज्यादा मजबूत करेगा। दर असल, अभी के समय में चीन ईरान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बाहरी खिलाड़ी बन गया है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, अमेरिकी प्रतिबंध के बाद सबसे बड़े तेल खरीदार के साथ उसका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है।

ब्रिटेन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा माध्यम से चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को समझने तथा उनका जवाब देने में ब्रिटेन की क्षमता में सुधार करेगा। मतलब साफ है कि वामपंथी विचारधारा वाली ब्रिटेन की नई सरकार का चीन के साथ संबंध पहले से और प्रगाढ़ ही होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चीन आपसी सम्मान और परस्पर सहयोग के आधार पर चीन-ब्रिटेन संबंधों को सही रास्ते पर बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के साथ काम करेगा। लेबर पार्टी और चीन के संबंधो के इतिहास में जाने पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री ब्लेयर के कार्यकाल को चीन के साथ आर्थिक संबंधों के सनहरे दौर की संजा दी गई थी। ब्रिटेन के मौजूदा हालात में चीन के साथ आर्थिक संबंध महत्त्वपर्ण हैं। आधुनिक विश्व में चीन की आर्थिक शक्ति, विशाल व्यापार और निवेश को ध्यान में रखा जाए तो ब्रिटेन के लिए चीन कितना जरूरी है, यह समझ में आता है। ये बातें स्टार्मर को 'भविष्य के लिए चीन' की उपयोगिता को दशार्ती हैं।

प्रतीत होता है कि ईरान भी चीन के साथ अपने संबंध पहले से और ज्यादा मजबूत करेगा। दर असल, अभी के समय में चीन ईरान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बाहरी खिलाड़ी बन गया है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, अमेरिकी प्रतिबंध के बाद सबसे बड़े तेल खरीदार के साथ उसका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। चीन के लिए ईरान का भू-रणनीतिक महत्व भी कम नहीं है। ईरान न केवल चीन के सबसे बड़े तेल प्रदाताओं में से एक है, बल्कि मध्य-पर्व, मध्य एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख संभावित ऊर्जा परिवहन केंद्र भी है। वैसे देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध एक रफा है। ईरान को चीन की जरूरत चीन से ज्यादा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएण्टिव रणनीति में ईरान की भूमिका उल्लेखनीय है, जो एशिया और मध्य -पूर्व के बीच ऊर्जा परिवहन के लिए एकीकृत प्रणाली बनाने की कोशिश में है। आने वाले समय में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन भारत के लिए परेशानी नहीं खड़ी करने वाला। यदि ब्रिटेन और ईरान, चीन के करीब आते हैं, तो भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के समीकरण में संभावित रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन लाने के साथ ही चीन के प्रभाव को भी बढ़ाएगा। हाल में भारत द्वारा प्रस्तावित भारत-मिडिल ईस्ट-यरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन अडंगा डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की काट के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को समर्थन दिया है। दोनों देशो के लिए फायदेमंद मजबूत एफटीए की वकालत के साथ उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर साथ काम करने की इच्छा जताई है। ब्रिटिश पीएम ने न केवल जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के मामलों पर भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है, बल्कि भारत- ब्रिटेन के बीच आदरपूर्ण रिश्ते को और गहरा करने पर भी बल दिया है, जो आगे चलकर भारत के साथ मजबूत संबंध रखने की गहरी सोच को दर्शाता है। खस्ताहाल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए भारत जैसे विशाल बाजार की उपयोगिता स्टार्मर के दिमाग में जरूर होगी। गौरतलब है कि पूर्व में लेबर पार्टी के नेता कश्मीर में मानवाधिकार और खालिस्तान जैसे मुद्दों पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर चुके हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म के बाद लेबर पार्टी के प्रमुख रहे जेरमी कोर्बिन ने बयान दिया था कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को खत्म किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत मामलों का समाधान होना चाहिए। इसी साल लेबर पार्टी से सालाना सम्मेलन में एक इमरजेंसी प्रस्ताव की पास किया था जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर जाने के अनुमति दी जानी चाहिए।

सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न तथा गौर करने वाली बात यह होगी कि दोनों देशों में नई सरकार का चीन के साथ कैसा संबंध रहने वाला है? क्या तेहरान और लंदन बीजिंग के साथ मजबत संबंधों के लिए अपनी विदेश नीति में बदलाव करने वाले है? यदि दोनों देशों के साथ चीन के रिश्ते और मजबूत होते हैं, तो विस्तारवादी सोच को निरेंतर बढ़ाते रहने वाला चीन भारत के साथ कैसा बर्ताव रखने वाला है? ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव घोषणापत्र में दावा किया है कि नई सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर ब्रिटेन और चीन के संबंधों का पूर्ण ऑडिट' कराएंगे। वह चीन के साथ संबंधों के प्रबंधन के लिए दीर्घचकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में दो देशों के चुनाव परिणामों ने पूरे विश्व को चौकाया है। पहला, ब्रिटेन का चुनाव, जिसमें लेवर पार्टी के अप्रत्याशित प्रदर्शन ने 14 सालों से सता में रही कंजर्वेटिव पार्टी को हराया। वहीं, ईरान में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कयान का कट्टरपंथी नेताओं को सत्ता से बाहर करना बहत कुछ कहता है। यहां एक और बात गौर करने वाली है कि इन दोनों देशों ने समय से पूर्व चुनावी समर में उतरने का फैसला किया था। ब्रिटेन में समय से पर्व चुनाव कराने का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का दांव उल्ट पड़ गया। वहीं, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्रातीम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद ईरान सरकार ने समय से पूर्व चुनाव करने का फैसला किया था। आश्वर्य की बात है कि दोनों ही देशों के चुनाव परिणाम उम्मीद से उलट आए हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों में सरकार बदलने के बाद भारत के संबंधों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है।

परंपरागत तरीके से निकला मुहर्रम का शाही जुलूस

गोरखपुर(जीकेबी)। मोहर्रम की 5वीं को इमामबाड़ा एस्टेट का शाही जुलूस शानो-शौकत के साथ परंपरागत तरीके से निकाला गया।

इमामबाड़ा एस्टेट के पश्चिम फाटक से शुरू हुआ यह जुलूस शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ वापस इमामबाड़ा एस्टेट पहुंचा। इस दौरान शहर में कई इलाकों में जुलूस का स्वागत किया गया। इसमें मौजूद लोगों ने करतब दिखाए और ढोल-ताशों की धुन पर झूमते नजर आए।

इमामाबाड़ा एस्टेट का शाही जुलूस शानो-शौकत के साथ सुबह 10 बजे अदनान फर्रुख शाह (मियां साहब) के साहबजादे सैय्यद अयान अली शाह के नेतृत्व में परंपरागत तरीके से निकाला। सबसे आगे एस्टेट का परचम और शहनाई बजाने वालों का जत्था मातमी धुन बजाता हुआ चल रहा था। इसके साथ ही घोड़े, बैंड और हाथों में लाठी व बल्लम लिए मियां साहब के सैनिकों की आठ पलाटून सड़क के दोनों तरफ चलती नजर आई।

आखिर में इमामबाड़ा एस्टेट का खास मोहर्रम की मातमी धुन बजाने वाले जत्थे के साथ सोने-चांदी का अलम लिए हुए खास लोगों का दल था।

▸ सीएम पोर्टल पर एलपीजी के खिलाफ शिकायत प्रकरण

एलपीजी कंपनी की तरफ से मंडल के 20 एजेंसी संचालकों को बुलाकर गैस सिलिंडर की लोडिंग पर रोक लगा दी गई। कंपनी की तरफ से शर्त रखी गई कि पहले नॉन फ्यूल रेवेन्यू (एनएफआर) का टारगेट एजेंसी संचालक पूरा करें, फिर उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। अगर सिलिंडर नहीं मिले तो लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पाएंगे।

बीस एजेंसियों के सिलेंडर पर एलपीजी की रोक

गोरखपुर (जीकेबी)। मंडल के कई गैस एजेंसी संचालकों ने एलपीजी कंपनी के खिलाफ सीएम पोर्टल और आपूर्ति विभाग से शिकायत की है। आरोप लगाया कि एलपीजी कंपनी की तरफ से मंडल के 20 एजेंसी संचालकों को बुलाकर गैस सिलिंडर की लोडिंग पर रोक लगा दी गई। कंपनी की तरफ से शर्त रखी गई कि पहले नॉन फ्यूल रेवेन्यू (एनएफआर) का टारगेट एजेंसी संचालक पूरा करें, फिर उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। अगर सिलिंडर नहीं मिले तो लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पाएंगे।

एलपीजी कंपनी और एजेंसी संचालक के बीच अनुबंध पत्र के दौरान यह साफ होता है कि एजेंसी संचालक अपनी मर्जी और सहमति से कंपनी के इन सामानों को भी खरीद सकता है। जरूरत पड़ने और ग्राहकों की मांग पर इसे एजेंसी भी दे सकती है या ग्राहक कंपनी से सीधे आकर खरीद लें। बुधवार को एलपीजी कंपनी आईओसीएल के खिलाफ पीपीगंज के एक गैस संचालक ने आईजीआरएस पोर्टल पर सीएम से शिकायत की है। आरोप लगाया कि वो पीपीगंज में लंबे समय से गैस एजेंसी का संचालन करते हैं। बुधवार को उन्हें भी बैठक में जाना था, लेकिन नहीं जा सके।

दोपहर बाद उन्हें पता चला कि उनके अलावा मंडल के करीब 20 एजेंसी संचालकों को गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। शर्त रखी गई है कि उन्हें एनएफआर के तहत 19 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलेंडर, 19 किलोग्राम नैनो कट, 5 किलोग्राम कॉमर्शियल और 2 किलोग्राम सिलेंडर की बुकिंग करनी है। कहा गया कि पहले एजेंसी संचालक सिलेंडर ट्राली, गैस लाइटर, पाइप, स्टोप, थर्मल स्टोप(चूल्हा) किचन अप्लायंसेस, फायर वॉल, (आग बुझाने वाला) के अलावा एक पेंट(निजी कंपनी) और एफएमसीजी के तहत कुछ सामानों की बुकिंग करनी होगी। इसी बुकिंग के बाद उन्हें सिलेंडर का लोड जारी किया जाएगा। इसी शर्त पर उनकी और अन्य एजेंसी संचालकों का सिलेंडर रोक दिया गया है।

आपूर्ति दफ्तर में भी की शिकायत

एक गैस एजेंसी संचालक ने आपूर्ति विभाग में भी लिखित शिकायत की है। शिकायत में बताया कि उनके गैस की डिलीवरी को एलपीजी कंपनी की तरफ से रोक दी गई है। ऐसे में अब गैस सिलेंडर की सेवा दे पाने में वो असमर्थ हैं। उन्होंने आपूर्ति विभाग में संपर्क कर एलपीजी कंपनी पर दबाव बनाकर उनके गैस को लोड को जारी करने की गुजारिश की है। मंडल एलपीजी प्रमुख रवि कुमार चंदेरिया ने बताया कि एलपीजी कंपनी की तरफ से किसी सामान के खरीदने के लिए बाध्यता नहीं दी गई है। किसी गैस एजेंसी के लोड को नहीं रोका गया है। एजेंसी संचालकों को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। सुरक्षा के तहत हॉकरों को घर-घर जाकर किचन में गैस सिलेंडर के प्रयोग और रखरखाव की जांच की जा रही है। इसके तहत अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ग्राहक या हॉकर एजेंसी संचालक या कंपनी से संपर्क कर सामानों को खरीद सकता है। लेकिन, इसके लिए, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राहक सिलेंडर की खरीदारी के समय सिर्फ रेगुलेटर और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा कंपनी या एजेंसी किसी भी अन्य सामान के खरीदारी का दबाव नहीं बना सकती है। ये गलत है। ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। इसकी जांच करवाई जाएगी। कंपनी की तरफ से भी उनकी जीओ मांगा जाएगा। देखें तो किस आधार पर उनकी तरफ से ऐसा किया गया, जिसकी शिकायत आई है।

सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थितियां

केन्द्र सरकार आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष उपलबध कराती है, लेकिन सवाल महज धन मुहैया कराने का नहीं बल्कि गांवों में आयुर्वेद और योग-केन्द्रों की स्थापना और वहां की सेवा के लिए योग्य है। चिकित्सकों की कमी का भी है, इसलिए एमबीबीएस के अतिरिक्त बीएमसएस और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। गांव स्तर पर होमियोपैथी और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र की जो कमी है। यदि उस पर जल्द कदम उठाए जाएं तो गांवों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कुछ सुझाव दिए गये हैं। इनमें जनरल मेडिसिन में एनडी या फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में स्नातक होना शामिल है। इन तीनों सुझावों पर कारगर ढंग से आगे बढ़ने पर गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की समस्या को दूर करने के लिए एक व्यवहारिक कदम उठाने की बात सालों से कहता आया है। यह फार्मूला है पांच साल की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को एक साल का विशेषज्ञता कोर्स कराया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती पर ऐसे डाक्टर बिना किसी हिचक के ग्रामीण क्षेत्राों में उनकी तैनाती पर ऐसे डाक्टर बिना किसी हिचक के ग्रामीण क्षेत्राों में अपनी बेहतर सेवाएं दे सकें, लेकिन इससे बात नहीं बनी, फिर केन्द्र सरकार ने एक दूसरा फार्मूला तैयार किया, जिसके तहत एमबीबीएस डिग्री धारी डाक्टरों को परास्नातक यानी एमएस या एमडी में दाखिला तभी मिलेगा जब गांव में तैनाती की अनिवार्य अवधिक के लिए वे हलफनामा लिखकर देंगे। सरकार ने एक बात इसमें और जोड़ दी कि जो एमबीबीएस डिग्री धारी छात्र हलफनामा लिखकर देंगे यदि उनके नम्बर कम भी होंगे, तब भी उन्हें एमएस या एमडी में प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार के इस लुभावने फार्मूले के बाद भी गांवों में सेवाएं देने वाले डाक्टरों में कोई खास रुचित नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब एक सवाल यह है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद जब एमबीबीएस डाक्टरों में गांवों में सेवा देने की रुचि नहीं बन पा रही है तो अब कौन-सा फार्मूला अपनाया जायेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बदतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक(आईपीएचएस) का उपयोग बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की तादाद, दवाओं का भंडारण, प्रयोग शाला क्षमता और स्वास्थ्य के लिए संसाधन के लिए किया जाता है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से 40151 सरकारी अस्पतालों की पड़ताल जो 2007 और 2022 में संशोधित मानको के आधार पर की गयी। इसके आधार पर तैयार की गयी। इसके आधार पर तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार 30362 अस्पतालों को सौमें से 80 से भी कम अंक हासिल हुए। इनमें से 17,190 अस्पतालों को 50 से कम अंक हासिल हुए। संसाधनों के मामले में सिर्फ 8, 089 अस्पताल 80 से ज्यादा अंक हासिल कर मानकों पर ठीक पाए गए। स्वास्थ्य मानकों के लिए 80 से ज्यादा अंक लाना जरूरी है, जिसमें पड़ताल के दौरान बनाई गई डाटा किट के लिए 25 अंक राज्यस्तरीय मूल्यांकन के मिलते हैं। मरीजों की प्रतिक्रिया के आधार पर पांच अंक दिए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर दस अंक। पांच अंक प्रयोगशाला जांच सुविधाओं और दवाओं के भंडारण के लिए दस अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से अस्पताल का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिसमें 80 से अधिक अंक लाना जरूरी होता है। पड़ताल की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों में बढ़त अंतर है। मसलन- ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीक-ाकरण। कैंसर स्क्रीनिंग, खून की जांच जैसी तमाम सुविधाओं का अभाव के साथ बिजली की समस्या आम है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों बिस्तरों का अभाव और वाओं के भंडारण सुविधा में कमी पाई गई। शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में चिकित्सकों और नर्सें की कमी एक बड़ी चुनौती है। देश के आठ हजार से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में 14 उन जांचों की भी सुविधा नहीं है जो नियम के मुताबिक होनी ही चाहिए।

नेशनल हल्थ प्रोफाइल के अनुसार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्राों में मात्र 900 चिकित्सक हैं। आबादी के हिसाब से 70 हजार लोगों पर एक चिकित्सक है। बिहार और झारखंड में 50 हजार की आबादी पर सिर्फ एक डाक्टर है।

सरकारी अस्पतालों की समस्याएं और उनकी दयनीय हालत के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्यों को सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने और बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ आयुष्मान आरोग्यमंदिरों को मानक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। गौरतलब है कोरोना महामारी के दौरान हासिल आभासी मूल्यांकन के अनुभव के आधार पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए एक मॉडल विकसित किया है, जिसे वर्चुअल रूप से इस्तेमाल किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक को सौंपी है। आजाती के 76 वर्षों में मुल्क के तकरीबन सात लाख गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आज भी भारी कमी के अलावा डाक्टरों की नियुक्ति जरूरत से बहुत कम है। महज तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को कुछ संतोषजनक कहा जा सकता है। राज्यों ने कुछ वर्ष पूर्व ग्रामों में चिकित्सकों की कमी को पूर्ण करने के लिए सख्त कानून निर्मित किए थे बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए अधिकांश चिकित्सक तैयार नहीं हैं। अकेले राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पिछले एक दशक में दस हजार से अधिक चिकित्सकेां ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने से मना कर दिया। भारत चीन की अपेक्षा ग्रामीण महज 3100 मरीजों पर एक बेड है। वहीं पर बिहार में, 18हजार ग्रामीणों पर एक बेड है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 3900 मरीज पर एक बेड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्राों में 2600 की आबादी पर एक एलोपैथिक डाक्टर है जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रत्येक एक हजार लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। भारत में तकरीबन दस हजार की आबादी पर बमुश्किल सात चिकित्सक हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के यहां पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्कों की कुल संख्या-लगभग एक करोड़ है। राज्यों में चिकित्सकों की उपलब्धता के प्रकरण में पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे खराब है।

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण

भारत-रूस की मैत्री का व्यापक महत्व है। यह पुराना मित्र देश का भारत की ताकत रहा है, मार्गदर्शक रहा है, हर सुख-दुःख का साथी रहा है। नेहरु युग से ही भारत-रूस के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य के बीच भी गहरा आत्मीय लगाव रहा है। भारतीय फिल्में रूस में बड़े चाव से देखी जाती रही है। कश्मीर के मसले पर भारत जब-जब अलग-थलग पड़ता रहा, तब तब रूस ने भारत का साथ दिया।

भारत-रूस की मैत्री को नये आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल मैत्री के धागों एवं द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को नये शिखर देने का प्रयास किया है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिये एक नए सोच के साथ नये सफर का आगाज है। एक ऐसे समय में, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को पश्चिमी देशों के विरोध के कारण रूस दुनिया में अलग-थलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत में पहले विदेश यात्रा के लिये रूस का चयन करके जता दिया है कि भारत-रूस की मैत्री अक्षुण्ण है और किसी भी तरह के दुनिया के दबाव में यह दोस्ती कमजोर नहीं पड़ने वाली है। भारत ने जहां मैत्री को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, वहीं अपने मित्र देश को युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपना स्पष्ट रुख भी जताया है। मोदी की इस यात्रा की एक बड़ी निष्पत्ति यह है कि रूस में अब दो नये वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से एवं ज्यादा बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने विरोध जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने मैत्री-मूल्यों को किसी भी दबाव में कमतर नहीं होने देगा। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके हो या अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी युद्ध विरोधी सोच के चलते ही यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। दुनिया में बन रही इस नई धारणा को तोड़ना जरूरी था, इसी दृष्टि से इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने का ध्येय था, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है।

खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में इस यात्रा को गहरी उत्सुकता से देखा जा रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है।

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत अब एक स्वतंत्र ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बड़े शक्तिशाली देशों के लिये भी भारत एक बाजार है। इसलिये भारत किसी भी दबाव में न आते हुए शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। रूस समर्थकों ने भले ही यह दशार्ना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश ह्यईर्ष्या से जल रहे हैंह्न, परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है।

यह यात्रा अनेक कारणों एवं दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रही, यात्रा के दौरान दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के समझौते तो हुए ही, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्र को मैत्रीपूर्ण सलाह देते हुए पूरी बेबाकी से कहा, युद्ध के मैदान से कोई हल नहीं निकलता ह्न यह प्रधानमंत्री मोदी का वैसा ही बयान है जैसा दो साल पहले समरकंद में पुतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था कि यह युद्ध का दौर नहीं ह । असल में भारत हमेशा से शांति के उजालों एवं युद्ध के अंधेरों से मुक्ति का ही समर्थक रहा है। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने बम-बंदूक के बजाय शांति-वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। मोदी ने साहस एवं निर्भयता से पुतिन को दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं, लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता जारी रखते हुए यह स्पष्ट करते रहना होगा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त होते हुए देखना चाहता है।

यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के भी हित में है। इसी के साथ भारत ने अपने मित्र देश को अपनी तकलीफ को साझा करते हुए यह एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई कि चीन के साथ उसकी नजदीकी परोक्ष रूप से पाकिस्तान को उत्साहित करती है, जो भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों को खाद-पानी मुहैया कराने का काम करता है।

रूस भारत के सहयोग के लिये तत्पर रहता है, इसबार भी यह खबर भी सुकून देने वाली है कि रूस ने भारत के आग्रह पर न केवल रूसी सेना के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भारतीयों की नियुक्ति रोकना स्वीकार कर लिया है बल्कि नियुक्त किए जा चुके युवाओं को स्वदेश भेजने पर भी मान गया है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सफल कूटनीति के एक उत्तम उदाहरण के रूप में याद रखी जाएगी।

भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था।

अन्य पहलू है, इस द्विपक्षीय रिश्ते में कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। विज्ञान-प्रौद्योगिकी और ह्यपीपुल-टु-पीपुल कॉन्टैक्टह्न यानी आम लोगों के स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाने पर रजामंदी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना। भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर इसकी एक बानगी है। अच्छी बात यह भी रही कि ईंधन के मामले में भारत को स्थिरता प्रदान करने में रूसी योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सराहना की, जो उचित भी था, क्योंकि अब हम खाड़ी देशों के बजाय सबसे अधिक तेल रूस से ही आयात करने लगे हैं।

भारत-रूस की मैत्री का व्यापक महत्व है। यह पुराना मित्र देश का भारत की ताकत रहा है, मार्गदर्शक रहा है, हर सुख-दुःख का साथी रहा है। नेहरु युग से ही भारत-रूस के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य के बीच भी गहरा आत्मीय लगाव रहा है। भारतीय फिल्में रूस में बड़े चाव से देखी जाती रही है। कश्मीर के मसले पर भारत जब-जब अलग-थलग पड़ता रहा, तब तब रूस ने भारत का साथ दिया। 1955 में रूस के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए कहा था, ह्यहम इतने करीब हैं कि अगर आप कभी हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे ह्न आश्वासन सिर्फ मुंहजबानी नहीं था बल्कि सोवियत संघ ने 1957, 1962 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों को वीटो कर दिया था, जिसमें कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात कही गई थी।

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भी जब पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका भारत पर लगभग आक्रमण करने ही वाला था, तब रूस द्वारा भारत के पक्ष में भेजी गई सैन्य सहायता ने ही अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया था। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी रूस का अनूठा योगदान रहा है। रूस ने ही भारत को सैन्य हथियारों व अन्य साजोसामान की आपूर्ति करके अपने दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ बनाया है। ऐसे भरोसेमंद देश के साथ जब बीच के दौर में आर्थिक कारणों व वैश्विक दबावों के चलते दूरी आने लगी थी तो दोनों ही देशों की जनता ने मांग उठायी कि ऐसे विश्वसनीय सहयोगी को खोना उचित नहीं होगा। मोदी की यात्रा से भारत-रूस संबंधों एवं मित्रता की नई इबारत लिखी गयी है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सुखद होने वाले हैं।

गठबंधन सरकार की नैतिकता के लिए पहले विद्वानों ने यह राय बनाई थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद महज सत्ता प्राप्ति के लिए किया गया जोड़-तोड़ जनता के साथ घोखा है। ऐसे में चुनाव पूर्व गठबंधन को नैतिक माना गया। चुनाव पश्चात के गठबंधन को मजबूरी। चुनाव बाद गठबंधन को अनैतिक नहीं बताया गया, क्याकि जनता पर चुनाव के खर्च का बोझ डालना सही नहीं रहेंगा। आप देख रहे होगे कि नैतिकता भी खर्च के हिसाब से पाला बदल लेती है। जिस समाज में दों तरह की नैतिकता हो, वह नैतिक रूप से भ्रष्ट समाज होता है। इधर मैं ये सोच रहा हं कि भारत हो या फ्रांस, ऐसी दोहरी निष्पक्षता या नैतिकता किसी पारटी या राजनीतिक समूह की कद तक रक्षा कर पाएंगे?

इंटरनेशनल इंग्लिश मींडिया एक हफ्ते से सांसत में था। अब जाकर उसे राहत मिली है। इंटरनेशनल इग्लिश मींडिया की अच्छी बात ये है कि अच्छे मौसम में वह निष्यक्ष' रहता है, लकिन मौसम प्रतिकूल होते ही वह अपने पसंदीदा दल के सिर पर हार की तलवार लटकता देख, निष्पक्षता का केचुल उतारकर उनके लिए परिष्कृत दुष्प्रचार शुरू कर देता है । पिछले एक हफ्ते में भारत में लोकप्रिय इंटरनेशनल इंग्लिश मीडिया दुबला हुआ जा रहा था कि 7 जुलाई के बाद फ्रांस में कहर आ जाएगा।

फ्रांस में दो चरण में चुनाव होता है। फ्रांस के चुनाव में पहले चरण में जो पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी वही दुसरे दौर के चुनाव के बाद तीसरे स्थान पर पहंचती दिख रही है। पहले चरण में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले दल दूसरे चरण के लिए आपस में मिल गए थे।

उन्होंने जनता से अपील की थी कि जिस सीट पर जो उम्मीदवार पहले चरण के नंबर वन दल को हराता दिखे, उसे ही वोट दें। दूसर चरण में पहले दल को हराने के लिए 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया। इतना सब करने के बावजूद सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को फ्रांस में बहुमत से कम मिलने का अनुमान है। याद रखें कि एक दल को नहीं, बल्कि कई दलों के गठबंधन को बहुमत से कम सीटे मिल रही हैं। बहुमत के लए इस तरह की रस्साकशी लोकतंत्र के लिए स्वाभाविक है। उल्ल्लेखनीय ये है कि फ्रांस का चुनाव भारत के चुनाव से तीन बिंदुओं पर मिलता दिख रहा है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। वे तीन बिंद हैं- हिंसा, नैतिक हार और गठबंधन सरकार।

इस समस्या के समाधान के लिए खास पदों पर ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसमें कई चरण में चुनाव से होते हैं ताकि अंतिम चरण में बस दो-तीन लोग बचे और जनता किसी एक को 50 प्रतिशत से ऊपर मत देने को बाध्य हो।

चीन में अगर एक पार्टी के तानाशाही है तो अमेरिका में दो दलों की तानाशाही है। चीन और अमेरिका का पॉलिटिकल मॉडल उत्तरी कोरिया, ईरान और कतर जैसे देशों से बेहतर है,लेकिन भारत, जर्मनी, प्रांस, ब्रिटेन का मॉडल अमेरिका और चीन से बेहतर है, जो बहुदलीय व्यवस्था को पोषण देता है। ये मॉडल यह मानकर नहीं चलता है कि कोई एक या दो दल ही, पूरे देश की बेहतरी के चौकीदार हैं। आजादी के खुमार से निकलने में भारत को करीब 45 साल लगे और 1989 में भारत में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला।

सबसे बड़े दल सरकार गठन से किनारा कर लिया। दूसरे बड़े दल ने तीसरे दल एवं अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वह करीब 11 महीने में गिर गई। उसके बाद सबसे बड़े दल ने एक छोटे से धड़े को बाहर से समर्थन देकर उसकी सरकार बनवा दी । इस विडंबना को किसी विद्वान ने नैतिक संकट नहीं बताया कि जिस दल के खिलाफ बड़े दल ने चनाव लड़ा था, उसको ही सरकार बनवा दी गई।1989 के ुनाव का सदेश था कि सबसे बड़ा दल सरकार चलाएगा तभी वह 5 साल चलेगी नहीं तो ऐसे ही हर साल नया प्रधानमंत्री मिलेगा। दो साल में दो सरकार गिरने के बावजूद देश की जनता ने 1991 के चुनाव में खुद को देश का डिफाल्ट रूलर समझने वाले दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 1991-92 के चुनाव में जिस दल को सबसे ज्यादा 244 सीटें मिली उसने बिना किसी गठबंधन के अगले 5 साल तक सरकार चलाई। संदेश साफ था कि या तो हमें बाहर से समर्थन दो या फिर पिछली बार की तरह 11 महीने वाले रैंटर पीएम के लिए तैयार रहो।

भारत की तरह फ्रांस में भी राष्ट्रपाति का पद आम चुनाव से प्रभावित नहीं होता, लेकिन वहां के राष्ट्रपति के पास हमारे राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। पहले चरण में चुनाव परिणाम इन्टरनेशनल मीडिया की चाहत के उलट आए तो सडकों पर हिंसा हो गई, दूसरे चरण में जब चुनाव चाहत के अनुसार आए तो भी हिंसा हो गई। फ्रांस और हमारे बंगाल के बीच यह अद्भुत समानता है कि हार की आशंका और हार टलने की खुशी, दोनों स्थितियों में हिसा हो जाती हैं। राहत की बात ये है कि बहमत सें सीट कम पान के बाद भी फ्रांस में सखसे बडे वामपंथी गठबंधन (जिसमें कई दल शामिल हैं) की 'नैतिक हार' नहीं होगी। बहुमत वाले प्राप्त करना लोकतांत्रिक देशों की समस्या है। चीन कतर और अफगानिस्तान में किसी को अल्पमत की तानाशाही से समस्या नहीं होती।

किसी एक पार्टी को बहमत न मिलने की भारत में पिछले 35 साल में किसी विद्वान ने 2024 से पहले नैतिक पराजय नहीं कहा था। जमनी, पफ्रांस, कनाडा इत्यादि में गठबंधन सरकारें चल रही हैं, लेकिन किसी विद्वान ने वहां की सरकार को नैतिक रूप से हारी हुई नहीं कहा।

जिन देशों में लोकतंत्र जितना मजबूत है, वहां किसी एक दल का बहुमत प्राप्त करना उतना कठिन है, क्योंकि वहां एक नहीं कई दल किसी न किसी इलाके या समुदाय के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं।

1991 में जिस दल ने बिना बहमत के अकेले दम पर पांच साल सरकार चलाई उस पर आजतक किसी ने अनैतिक सरकार होने का आरोप नहीं लगाया। विद्वान उसे अल्पमत की सरकार कहते हैं।

1996 में सबसे ज्यादा 161 सीट जीतने वाले को विपक्ष में बैठना पड़ा। 140 सीटें जीतने वाले दूसरे बड़े दल ने विपक्ष में बैठकर भी तीसरे बड़े दल का प्रधानमंत्री बनवा दिया,जिसे महज 46 सीटों पर जीत मिली थी, जो कुल सीटों की 10 प्रतिशत भी नहीं था। यानी तकनीकी तौर पर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए जरूरी 55 सीटों ने से भी कम सीट पाने वाले दल ने करीब दो साल देश में सरकार चलाई, लेकिन 11 महीने वाला पुराना रेटर सिस्टम जारी रहा। इस पूरी कवायद को विद्वानों ने अनैतिक घोषित नहीं किया। इसे लोकतंत्र की माया या त्रिशंकु संसद बताया। 1998-1999 में जो दल सबसे बड़ा बनकर उभरा उसने बाहर से समर्थन के लेन-देन के रेंटल सिस्टम को नकारते हुए दो दशक पुराना नुस्खा नए एंगल से अपनाया। 1977 में कई दलों ने आपस में विलय कर लिया था तो इस बार उन्होंने विलय करने के बजाय गठबंधन बनाकर एक गुट बनाया। विद्वानों ने इसे भी अनैतिक नहीं माना और गठबंधन युग के आगाज की मुनादी करवा दी। सरकार छह साल चली। 1996 में जिस दसरे बड़े दल ने 140 सीटे जीतकर सरकार नही बनाई थी उसी दल ने 2004 में महज 145 सीटें जीतकर सरकार बना ली।1989 और 1996में उसने साफ संदेश दे दिया था कि हमारा पीएम नहीं रहेगा तो 11 महीने का रेन्टर पीएम सिस्टम सहना पडेंगा। नतीजा ये हुआ कि महज सबसे बड़े दल ने महज 145 सीटो के साथ आराम से 5 साल गठबंधन सरकारचलाई, लेकिन किसी विद्वान ने इसे अनैतिक नहीं कहा।

इसे गठबंधन यूग का नया अध्याय कहा। 2004 मं दसरे बड़े दल को 138 सीटों पर जीत मिली थी यानी उसे सबसे बड़े दल से केवल 7 सीटे कम मिली थी, लेकिन वे सात सीटे उन मौसरे भाइयों जैसी साबित हुई जिनमें 7 दिन पहले पैदा हुए भाई को आजीवन भैया कहना पड़ता है।

दूसरा बड़ा दल अगले पाच साल तक भइया-भइया कहता रहा लेकिन यह कभी न कह सका कि भैया आपकी नैतिक हार हई है आपकी सरकार अनैनिक है। दूसरा दल तो छोड़िए किसी बड़े विद्वान ने इस प्र-क्रिया को अनैतिक घोषित नहीं किया बल्कि गठबंधन को देशहित में बताया। 5 साल राज करने के बाद भी सत्ताधारी दल क 2009 में बहुमत से 66 सीटे कम मिलीं तो भी किसी ने नहीं कहा कि आपको अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला इसलिए यह नैतिक हार है और जनता ने आपको नकार दिया है।

बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों और सेवाओं पर दबाव

वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या आठ अरब 11 करोड़ 88 लाख के लगभग है जो वर्ष 2023 से 0.91 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या एक अरब 44 करोड 17 लाख है जो वर्ष 2023 से 0.92 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन को पीछे छोड़ कर विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 51 लाख है। जनसंख्या में वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाब डालती है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, उस गति से आर्थिक विकास एवं अन्य विकास नहीं हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या के रूप में बड़ी चुनौती है।

बात जब जनसंख्या वृद्धि की हो रही है तो दुनिया में भारत की बढ़ती जनसंख्या न केवल चौंका रही है, बल्कि एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हो गया है, परेशानी में डालने वाली इस खबर के प्रति सचेत एवं सावधान होने के साथ सख्त जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की अपेक्षा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2023 में ही चीन से ज्यादा आबादी वाला देश हो गया था। जबकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2027 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। बढ़ती जनसंख्या की चिन्ता में डूबे भारत के लिये चार साल पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होना कोई गर्व की बात नहीं है। भारत के लिये बढ़ती आबादी एवं सिकुड़ते संसाधन एक त्रासदी है, एक विडम्बना है, एक अभिशाप है। क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है किंतु इसके नियंत्रण के लिये कोरे कानूनी तरीके को एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। इसके लिए सरकार को जनसंख्या पर तुरंत पारदर्शी एवं सख्त नियंत्रण के कदम उठाने के साथ, भारत के लिए प्रभावी जनसंख्या नीति को लागू करना, आम जनता की सोच एवं संस्कृति में बदलाव लाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की 61 फीसदी हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि जहां कम आबादी है, वहां ज्यादा संपन्नता है। भारत में दिन-प्रतिदिन जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसी से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ने का कारण यही है, संसाधनों की किल्लत भी इसी से बनी हुई है। यही एक कारण भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। इसलिए सरकार शीघ्र सुसंगत जनसंख्या नीति लागू करे। जिसको दिक्कत हो और ज्यादा बच्चे पैदा करके मनमानी करनी हो, उनके खिलाफ कानूनी सजा के प्रावधान किये जाये। यह एक अराष्ट्रीय सोच है कि अधिक बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगी कष्ट में झोंकना। जब बच्चे को सुखी जिंदगी नहीं दे सकते, तो दूसरों के भरोसे उन्हें पैदा करने की प्रवृत्ति शर्मनाक है। यह देखने में आ रहा है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ समुदाय बच्चे पैदा करने को लेकर रूढ़िवादी नजरिया अपनाए हुए हैं और उनकी प्रतिक्रिया में अन्य समुदायों के नेता भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करने लगे हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। इस तरह जनसंख्या बढ़ोतरी की पैरोकारी करने वालों की निंदा की जानी चाहिए, चाहे वे किसी मजहब के हों। क्योंकि देश की तरक्की की सबसे बड़ी बाधा बढ़ती जनसंख्या ही है। भारत में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में राजनीति एवं तथाकथित स्वार्थी राजनीतिक सोच बड़ी बाधा है। अधिकांश कट्टरवादी मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का अनुचित लाभ लेने के लिए अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिये सर्वाधिक इच्छुक रहते हैं और इसके लिये कुछ राजनीतिक दल उन्हें प्रेरित भी करते हैं। ऐसे दलों ने ही उद्घोष दिया है कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी सियासत में उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनसंख्या के सरकारी आकड़ों से भी यह स्पष्ट होता रहा हैं कि हमारे देश में इस्लाम सबसे अधिक गति से बढ़ने वाला संप्रदाय-धर्म बना हुआ हैं। इसलिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि ये कट्टरपंथी अपनी जनसंख्या को बढ़ा कर देश के लिये बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। सीमावर्ती प्रांतों जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, कश्मीर आदि में वाकायदा पडौसी देशों से मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जाती है और उन्हें देश का नागरिक बना दिया जाता है, यह एक तरह का 'जनसंख्या जिहाद' है क्योंकि इसके पीछे इनका छिपा हुआ मुख्य ध्येय हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत का इस्लामीकरण किया जाये। हमारी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां बहुत उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जरूरत के हिसाब से थाम नहीं पाए। चीन ने साल 1979 में ही एक संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू कर दिया था, इसका नतीजा हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की जरूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसंख्या लगभग 16.90 करोड़ थी।

तार्किक पाठ्यक्रम समय की मांग

एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव कर रहा है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सामग्री का संशोधन पाठ्यक्रम के लिए समान होना चाहिए। लेकिन भारत में स्कूली पाठ्यक्रम हमेशा नवीनतम शोध के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। पक्षपातपूर्ण या संकीर्ण दृष्टिकोण से बचने के लिए स्वतंत्रता के बाद से, हमारी स्कूली पाठ्यपुस्तकें अक्सर कला, साहित्य, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में भारत की प्रगति को मान्यता देने से बचती हैं। पहले की पाठ्यपुस्तकें भारतीय इतिहास के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण बनाती हैं जो विश्व की सभ्यता पर भारत के गहन प्रभाव को दबा देता है। इसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक कथा के बारे में एक विषम धारणा बनती है। स्कूली छात्रों को कम उम्र में ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षों की आक्रामकता के संपर्क में लाना उन्हें संकट में डाल सकता है। स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा के अनुचित चरणों में ऐतिहासिक संघर्षों का परिचय, बच्चों के दिमाग में व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ की कमी की धारणा को अमर कर सकता है। एक संतुलित कथा बच्चों के दिमाग में दुश्मनी और पूर्वाग्रह पैदा करने के जोखिम को कम करती है।

कुल मिलाकर पाठ्यपुस्तकों से हटाई जाने वाली सामग्री, भारत के भूतकाल और वर्तमान की नकारात्मक धारणा पर आधारित है। यह मानसिकता कमजोर है, और केवल कुछ को हटाकर अपने इतिहास को बदलने का प्रयास करती है। इनके लिए भारतीय इतिहास के रचनात्मक, समावेशी, तार्किक, सुसंगत और विद्यार्थी अनुकूल संस्करण को लाना असंभव था, क्योंकि रचना में एक सकारात्मक गुण है, जिसे राजनीतिक ताकतें अक्सर कम आंकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास में एकपक्षीय दृष्टिकोण से आगे बढ़कर चिंतन और तार्किक पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। एनसीईआरटी से अपेक्षा है कि वह वर्तमान विवाद से अप्रभावित रहते हुए छात्रों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करेगी, न कि तथ्यों के चयन में छात्रों को उलझाएगी।

एकतरफा ऐतिहासिक तथ्य स्कूली बच्चों के बीच सामाजिक सामंजस्य और आपसी सम्मान में बाधा डालेंगे। सार्थक पाठ्यपुस्तक संशोधनों का विरोध एक पुरानी संकीर्ण वैचारिक विचार प्रक्रिया को दर्शाता है, जो भविष्य में ऐतिहासिक शिकायतों और शत्रुता को शाश्वत बनाता है। एक संतुलित, विश्वसनीय और भरोसेमंद ऐतिहासिक कथा, संघर्ष समाधान और आपसी सम्मान के सकारात्मक उदाहरणों को रेखांकित करती है। यह छात्रों को अपने जीवन में सकारात्मक उदाहरणों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रेरित करती है। स्कूली छात्रों को एक संतुलित इतिहास पढ़ाना जो संघर्ष-आधारित कथाओं को कम करता है, उन्हें भारत की विरासत के बारे में बेहतर जानकारी के साथ जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नागरिक बनने में सक्षम बनाता है। ऐसी पाठ्यपुस्तकें बच्चों में संज्ञानात्मक और भावनात्मक आधार बनाती हैं, जो भविष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। संतुलित कथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने का कोई भी प्रयास अंत नहीं बल्कि एक शुरूआत है। छात्रों को ऐसी संतुलित पाठ्यपुस्तकों से जो आधार मिलता है, वह उन्हें बाद के वर्षों में एक गहरी ऐतिहासिक समझ बनाने में मदद करेगा। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को छात्रों की उभरती जरूरतों को पूरा करने में उत्तरदायी होने के लिए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।

पाठ्यपुस्तकों में क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए, इसकी चर्चा लगातार होती रही है, क्योंकि स्कूल की पाठ्यपुस्तकें ही वह माध्यम हैं, जिनके द्वारा सुविधाजनक विमर्श को आगे बढ़ाया जा सकता है। विवाद तब होता है, जब एक विमर्श आपके लिए सुविधाजनक होता है और दूसरे वर्ग के लिए असुविधाजनक। वर्तमान में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में किए गए कुछ बदलावों से संबंधित विवाद को भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए, जब एक वर्ग का सुविधाजनक दृष्टिकोण दूसरे वर्ग के विमर्श के अनुरूप नहीं होता है। देखा जाए तो इस प्रकार का विवाद पहली बार नहीं हुआ है। भारत के शैक्षणिक इतिहास में इस प्रकार के विवाद पहले भी होते रहे हैं। विश्व भर की शिक्षा व्यवस्थाएं अपने-अपने देश के पाठ्यक्रम को समझ और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित बनाना चाह रही हैं, वहीं हमारे देश में विवाद इस बात पर हो रहा है कि किस पक्ष का तथ्य सही है? यहां असुविधाजनक तथ्य को वृत्तांत की सहायता से सदैव छुपाने का प्रयास रहता है। इतिहास को न केवल तथ्यों से समझा जा सकता है और न केवल वृत्तांतों से। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों का उचित मात्रा में समावेश हो, मगर हमारे देश में इतिहास लेखन की शैली में तथ्य और वृत्तांत का विभाजन काफी बारीक है। इस विषय के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। जहां पूरे विश्व की शैक्षणिक व्यवस्थाएं अपने स्वरूप को बदल रही हैं और छात्रों को तथ्यों से भरने के बजाय उन्हें इतिहास आधारित दृष्टिकोण से युक्त करने पर जोर दे रही हैं, जिससे छात्रों में इतिहास के प्रति एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित हो सके। आज के तकनीकी दौर में इतिहास बोध होने पर छात्र स्वयं ही ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल कर सकता है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह अपने छात्रों को तथ्य आधारित, वस्तुनिष्ठ पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराए, क्योंकि यही छात्र भविष्य के विमर्श को न केवल आगे बढ़ाते हैं, अपितु नए विमर्श की शुरूआत भी करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास में एकपक्षीय दृष्टिकोण से आगे बढ़कर चिंतन और तार्किक पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। एनसीईआरटी से अपेक्षा है कि वह वर्तमान विवाद से अप्रभावित रहते हुए छात्रों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करेगी, न कि तथ्यों के चयन में छात्रों को उलझाएगी। पाठ्यपुस्तकें किसी देश की सरकार द्वारा दिया गया आधिकारिक कथन होती हैं। इस रूप में ये वैचारिक या सैद्धांतिक परियोजना होती है। इतिहास और राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण वैसे भी अधिक संवेदनशील होता है। ये विषम समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर विचार करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को इतिहास के पलड़े पर तौलकर, इतिहास और वर्तमान के बीच तार्किक सामंजस्य बनाना सिखाते है। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी देश-विदेश के सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार बनाने का प्रयत्न करता है। एनसीईआरटी की मूल पुस्तकों को इसी विचार के साथ रूप दिया गया था। कुल मिलाकर पाठ्यपुस्तकों से हटाई जाने वाली सामग्री, भारत के भूतकाल और वर्तमान की नकारात्मक धारणा पर आधारित है। यह मानसिकता कमजोर है, और केवल कुछ को हटाकर अपने इतिहास को बदलने का प्रयास करती है। इनके लिए भारतीय इतिहास के रचनात्मक, समावेशी, तार्किक, सुसंगत और विद्यार्थी अनुकूल संस्करण को लाना असंभव था, क्योंकि रचना में एक सकारात्मक गुण है, जिसे राजनीतिक ताकतें अक्सर कम आंकती हैं।

-प्रियंका सौरभ

अपनी सादगी और संजीदगी से दर्शकों का दिल जीतने वाले थे संजीव कुमार

09 जुलाई को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अभिनय करने का सपना देखा था। यही कारण रहा कि जब वह पर्दे पर आए, तो हर कोई उनके अभिनय, सादगी और संजीदगी का कायल हो गया। वह हर किरदार को इतनी शिद्दत के साथ निभाते थे कि दर्शक खुद को उससे जुड़ा हुआ पाते थे। तो आइए जानते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर संजीव कुमार के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

जन्म और परिवार- गुजरात के सूरत में 09 जुलाई 1938 को संजीव कुमार का जन्म हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कलाकार बनने का ख्वाब देखा था। हालांकि वह गुजराती परिवार से थे, लेकिन उनके जन्म के करीब 7 साल बाद संजीव कुमार का परिवार मुंबई आकर बस गया था। वहीं अभिनेता बनने का ख्वाब देखने वाले संजीव कुमार ने मुंबई में थिएटर ज्वॉइन कर लिया।

बॉलीवुड में एंट्री- थिएटर करने के दौरान साल 1960 में संजीव कुमार ने फिल्म 'हम हिंदुस्तानी' से बड़े पर्दे पर कदम रखा और इस फिल्म के साथ ही संजीव कुमार भी रातोंरात स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। संजीव कुमार खुद को किसी भी किरदार में इतनी शिद्दत से ढालते कि जब वह पर्दे पर दिखते तो दर्शक उन्हें देखते ही रह जाते थे।

प्यार को तरसे- अपनी एक्टिंग और सादगी से लाखों-करोड़ों दिलों को जीतने वाले संजीव कुमार रियल लाइफ में हमेशा प्यार को तरसते रहे। दरअसल, वह ड्रीम गर्ल यानी की हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। इतना ही नहीं अपने प्यार को मुकम्मल करने और हेमा मालिनी का हाथ मांगने उनके घर भी गए। लेकिन हेमा मालिनी की मां ने इस रिश्ते को यह कहकर इंकार कर दिया कि उनकी बिरादरी अलग है। इस इंकार से अभिनेता इस कदर टूटे कि उन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला ले लिया।

मौत- बता दें कि अभिनेता संजीव कुमार अपनी मौत को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। अक्सर वह कहते थे कि वह ज्यादा लंबा नहीं जी पाएंगे। वह 50 साल पूरे करने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। दरअसल, इस बात के पीछे वह अपने पारिवारिक हिस्ट्री का हवाला दिया करते थे। वह कहा करते थे कि उनके परिवार के सभी मर्दों 50 साल से पहले ही निधन हुआ है। अब इसको अंधविश्वास कहा जाए, या हकीकत लेकिन महज 47 साल की उम्र में 06 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

हर तरह का किरदार निभाने वाली बॉलीवुड अदाकारा

बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाएं हैं। कुछ ने रोमांस किया, तो वहीं कुछ हसीनाओं ने एक्शन सीन भी किए हैं। आज उन्हीं अभिनेत्रियों की बात करने जा रहे हैं, जिन्में से कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्मों और वेब सीरीज में एक्शन किया है, तो कुछ अभी आने वाली फिल्मों में एक्शन करती नजर आएंगी।

करीना कपूर खान की फिल्म 'क्रू' इस साल रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इस साल उनकी दूसरी फिल्म 'सिंघम अगेन' आने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'सिंघम अगेन' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज बना हुआ है। इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह नजर आएंगे। इस मल्टीस्टारर फिल्म में करीना और दीपिका दोनों ही धांसू एक्शन करती नजर आएंगी।

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'द ब्लफ' को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में प्रियंका जमकर एक्शन करती नजर आएंगी। हाल ही में प्रियंका ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी एक तस्वीर साझा की थी और बताया था कि इस फिल्म में एक्शन सीन करते वक्त उन्हें कितनी खरोंच लगी हैं। वैसे यह पहली बार नहीं है, जब प्रियंका किसी फिल्म में एक्शन करती नजर आएंगी। इससे पहले भी प्रियंका ने वेब सीरीज 'सिटाडेल' में जमकर एक्शन किया था। जानकार सूत्रों के अनुसार, वेब सीरीज 'सिटाडेल' के हिंदी रुपांतरण में सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की जोड़ी तहलका मचाती नजर आएगी। इस सीरीज में सामंथा जमकर एक्शन करती नजर आएंगी। वैसे पहले कई फिल्मों में सामंथा एक्शन करती नजर आ चुकी हैं। फिल्म 'यशोदा' में सामंथा ने जमकर एक्शन किया था।

दिशा पाटनी अपने गलैमरस अंदाज के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी चर्चा में बनी रहती हैं। दिशा 27 जून को रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में रॉक्सी के किरदार में धमाकेदार एक्शन करती नजर आईं। दिशा वैसे भी कई फिल्मों में एक्शन का तड़का लगा चुकी हैं। दिशा ने हाल ही में अपनी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का बीटीएस वीडियो साझा किया था, जिसमें वह गुंडों की पिटाई करती हुई दिखाई दीं।

कैटरीना कैफ फिल्म 'टाइगर' की अब तक की तीनों फ्रेंचाइजी में बदमाशों की पिटाई करती नजर आ चुकी हैं। कैटरीना का 'टाइगर 3' का टॉवल में एक्शन सीन काफी चर्चा में रहा था। फिल्म में कैटरीना ने जमकर एक्शन सीन किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म में कैटरीना के अलावा सलमान खान और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई थी।

आलिया भट्ट ने कुछ ही दिनों पहले अपनी आगामी वाईआरएफ की फिल्म 'अल्फा' का एलान सोशल मीडिया हैंडल पर किया था। बहरहाल, आलिया इन दिनों 'अल्फा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। बता दें कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स फीमेल लीड पर पहली बार फिल्म लेकर आ रहा है 'अल्फा'। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्में में आलिया एक सुपर-एजेंट के किरदार में नजर आने वाली हैं। आलिया के साथ इस फिल्म में 'मुंजा' अभिनेत्री शरवरी वाघ भी नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया और **शरवरी** दोनों ही फिल्म में जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी।

आखिर बाबा के पांव की धूल में कौन सा कल्याण निहित है?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट मांगी थे। वह उन्हें मिल चुकी होगी। वह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में भी घायलों का हाल-चाल पूछा। हाथरस में भगदड़ के मामले में यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजन में शामिल छः लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि एक लाख का इनामी मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर फरार है। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिह आयोग के सदस्य हैं। टीम दो महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सुझाव भी देगी। बाबा कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। कब तक वह भूमिगत रहेंगे। आखिर प्राथमिकी में उनका नाम क्यों नहीं है। एक इनसान और देश के नागरिक की कीमत 2.4 लाख रुपए नहीं है। मुद्दा और सवाल समुचित व्यवस्था और संवेदनशीलता का है। अंधविश्वास को लेकर हम किसी कुछ भी राय नहीं दे सकते। आखिर बाबा के पांव की धूल में कौन सा कल्याण निहित है?

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कथित भोले बाबा का समागम सामूहिक मौत में तब्दील हो गया। एक स्वयंभू के श्रद्धालुओं में पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अफसर भी शामिल हैं। हाथरस जिले के समागम में तब भगदड़ मच गयी, जब गरीब, आम आदमी, महिला आदि भक्त भोले बाबा केपांव छूना चाहते थे। भीड़ में आशीर्वाद की होड़ लगी थी। होड़ ही भगदड़ में तब्दील हो गयी। भीड़ में इतनी हड़बड़ी थी कि लोगों ने इनसानों को ही कुचल दिया। कितने घर अनाथ हो गये। सवाल यह है कि प्राथमिकी में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है। बताया जाता है कि करीब 1.25 लाख की भीड़ आई थी। दूसरा पक्ष 2.5 लाख की भीड़ का दावा कर रहा है। संख्या को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, इलाके के आईजी, डीएम और एसडीएम आदि के अलग-अलग बयान हैं। एडीजी ने दावा किया है कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। क्या इस छोटे से गांव में भीड़ का सैलाब देखकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नहीं हुई, लिहाजा बंदोबस्त नहीं किए जा सके। एसडीएम दफ्तर का कहना है कि 50 हजार की भीड़ बताई जा रही थी, लेकिन 80 हजार से ज्यादा लोग पहुंच गए। स्थानीय पुलिस का कहना हे कि हमें कार्यक्रम का जो पत्र मिला था, उसमें भीड़ का कालम खाली था। ऐसे धार्मिक बाबाओं के आयोजन में लोग आस्था और कष्ट निवारण की भावना के साथ आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसी भोले बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में समागम किया था। उसमें भी खूब भीड़ जुटाई गयी थी। सरकार और प्रशासन ने उस सत्संग की इजाजत कैसे दे दी थी।

घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह, हृदयविदारक, विचलित करने वाला था कि पुलिस कर्मी रवि यादव को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गयी। हम कथित भोले बाबा को बुनियादी गुनहगार मानते हैं। वह और उसके सेवादार तो अस्पताल तक नहीं पहुंचे कि उनके श्रद्धालु जीवित हैं अथवा दिवंगत हो गए।

फिलहाल आगामी दिवसों में जांच के बाद किसी के सिर पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जाएगा। परन्तु इन मौतों का कसूरवार कौन है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कमी कैसे पूरी होगी। बताया जाता है कि प्रवचन करने वाले बाबा नदारद हैं। कहा जा रहा है कि यह एक निजी कार्यक्रम था, कानून व्यवस्था के बलए प्रशासन की ड्यूटी लगायी गयी थी, लेकिन आयोजन स्थल पर भीतरी व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जानी थी। बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन हकीकत है कि हम पिछ्ले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए? दो साल पहले माता वैष्णों देवी के परिसर में भगदड़ में बारह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इंदौर में पिछ्ले साल रामनवमी के दिन बावड़ी की छत गिरने से 35 लोग मर गये थे। इसी तरह 2016 में केरल के कोल्लम के एक मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत हुई और दो सौ से अधिक घायल हुए थे। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन देख रहे साथ लोगों के ट्रेन से कुचल कर मरने की घटना को नहीं भूल पाए हैं।

वर्तमान युग विज्ञान का है। बच्चों को शुरू से ही चमत्कार और अंधविश्वासों से दूर करना होगा। सच्चे साधु संतों का सम्मान और श्रद्धा तो अच्छी बात है परन्तु जादू टोना और चमत्कार जैसे अंधविश्वासों से दूर रहना होगा। संचार के माध्यमों के जरिये ढोंगी बाबाओं की पोल खोलनी चाहिए। फर्जी बाबाओं पर लगाम के लिए प्रशासन के साथ आम जनता को भी सक्रिय होना पड़ेगा। हर भगवाधारी, तिलकधारी या भभूत लगाए आदमी को बाबा मान लेना एवं उसका यशोगान करना ठीक नहीं है। फर्जी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। सरकार को फर्जी बाबाओं पर लगाम के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और सख्त सजा का प्रावधान रखना चाहिए। मीडिया को भी फर्जी बाबाओं के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए। देश में भीड़ की भगदड़ से होने वाले 70 फीसदी हादसे धार्मिक आयोजनों के दौरान ही होते हैं। इसे रोकने को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, प्रशासन एवं आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए गए थे जिसके लिए भीड़ प्रबंधन से जुड़े लोगों की क्षमता विकसित करने एवं बेहतर प्रशिक्षण का सुझाव शामिल था। प्रशासन से भीड़ के व्यवहार एवं मनोविज्ञान का अध्ययन कर भीड़ प्रबंधन की बेहतर तकनीक विकसित करने को कहा गया था, जिसमें तिरुपति मंदिर हेतु आईआईएम अहमदाबाद की व्यवस्था की केस स्टडी भी शामिल थी। पुलिस को भी सख्ती के बजाय अच्छे व्यवहार के लिए कहा गया था। परन्तु रिपोर्ट का आज भी जमीन पर असर होता नहीं दिख रहा है।

वर्तमान युग विज्ञान का है। बच्चों को शुरू से ही चमत्कार और अंधविश्वासों से दूर करना होगा। सच्चे साधु संतों का सम्मान और श्रद्धा तो अच्छी बात है परन्तु जादू टोना और चमत्कार जैसे अंधविश्वासों से दूर रहना होगा। संचार के माध्यमों के जरिये ढोंगी बाबाओं की पोल खोलनी चाहिए। फर्जी बाबाओं पर लगाम के लिए प्रशासन के साथ आम जनता को भी सक्रिय होना पड़ेगा। हर भगवाधारी, तिलकधारी या भभूत लगाए आदमी को बाबा मान लेना एवं उसका यशोगान करना ठीक नहीं है।

डिजिटल अटेंडेंस को लेकर वाराणसी में बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का प्रदर्शन, जताया विरोध

विद्यालय परिसर में मुंडन कार्यक्रम का भोज प्रकरण

बिना अनुमति कार्यक्रम संपन्न कराया जाना पड़ा भारी

प्रधानाध्यापिका ने थाने में दी तहरीर

प्रधानाध्यापिका ने मुंडन संस्कार का प्रीति भोज करा रहे व्यक्ति के खिलाफ थाने में की शिकायत है। बिना अनुमति कार्यक्रम करने का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापिका सुषमा निषाद की तहरीर के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय सिंदुरिया प्रथम परिसर में बिना अनुमति के ग्राम सभा निवासी व्यक्ति की ओर से विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर मुंडन कार्यक्रम के प्रीति भोज के लिए विद्यालय परिसर में पांडाल लगाया गया। थाना प्रभारी सिंदुरिया दिनेश कुमार का कहना है कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

महाराजगंज (जीकेबी)। मिठौरा क्षेत्र के ग्राम सभा सिंदुरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर रविवार की शाम को विद्यालय परिसर में मुंडन कार्यक्रम का भोज चल रहा था।

स्कूल के सामने से गुजर रहे जिलाधिकारी ने देखा तो बीएसए को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। गत रविवार शाम को सिंदुरिया प्राथमिक विद्यालय प्रथम परिसर में ग्राम सभा निवासी व्यक्ति के यहां मुंडन संस्कार का प्रीति भोज का कार्यक्रम चल रहा था।

तभी निचलौल से महराजगंज की तरफ जा रहे जिलाधिकारी अनुनय झा की नजर विद्यालय परिसर के बाहर लगे गेट और अंदर लगाए गए पांडाल पर पड़ी।

उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी ली तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति के यहां मुंडन संस्कार है उसी का शाम को प्रीति भोज का कार्यक्रम है। जिलाधिकारी ने बीएसए श्रवण कुमार को फोन कर मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी मिठौरा को फोन कर मामले से अवगत कराया तो खंड शिक्षा अधिकारी मिठौरा शिव कुमार ने प्राथमिक विद्यालय प्रथम की प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण तलब किया।

प्रधानाध्यापिका सुषमा निषाद ने बताया कि इस संबंध में हमें जानकारी नहीं थी। विद्यालय गेट का ताला तोड़कर कार्यक्रम कराया जा रहा था। अधिकारियों का फोन आने के बाद हमें जानकारी हुई है। खंड शिक्षाधिकारी मिठौरा शिव कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सिंदुरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर कार्यरत प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उचित जवाब नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित

महराजगंज( )। मिठौरा क्षेत्र के सिंदुरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर रविवार की शाम को मुंडन संस्कार का प्रीति भोज कार्यक्रम हो रहा था। मंगलवार को मामले में बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है।

मामला यह है कि रविवार शाम को सिंदुरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम परिसर में ग्राम सभा निवासी व्यक्ति के यहां मुंडन संस्कार का भोज का कार्यक्रम चल रहा था। तभी निचलौल से महराजगंज की तरफ जा रहे जिलाधिकारी की नजर विद्यालय परिसर के बाहर लगे गेट और अंदर लगाये गये पंडाल पर पड़ी।

उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी तो पता चला गांव में एक व्यक्ति के यहां मुंडन संस्कार है उसी का शाम को प्रीति भोज का कार्यक्रम है। मामले में बीईओ मिठौरा शिव कुमार ने प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण तलब किया था। मामले में तथ्यों को रोड़-मरोड़कर पेश करने पर बीएसए श्रवण कुमार ने प्रधानाध्यापिका सुषमा को मंगलवार को निलंबित कर दिया।

▶ आम आदमी के लिए पहेली बना नया कानून,

धाराओं को लेकर भ्रमित अधिवक्ता

कुछ प्रचलित नई व पुरानी धाराएं

जुर्म	आईपीसी	बीएनएस
हत्या	धारा 302	धारा 103
हत्या का प्रयास	धारा 307	धारा 109
गैर इरादतन हत्या	धारा 304	धारा 105
दहेज हत्या	धारा 304-बी	धारा 80
चोरी	धारा 379	धारा 303
दुष्कर्म	धारा 376	धारा 64
छेड़छाड़	धारा 354	धारा 74
धोखाधड़ी	धारा 420	धारा 318
लापरवाही से मौत	धारा 304-ए	धारा 106
आपराधिक षडयंत्र	धारा 120बी	धारा 61
मानहानि	धारा 499, 500	धारा 356
लूट	धारा 392	धारा 309
डकैती	धारा 395	धारा 310
महिला हिंसा	धारा 498ए	धारा 85

गिरफ्तारी की सूचना देना होगा अनिवार्य

पुलिस के पकड़ कर ले जाने के मामले में काफी असमंजस की स्थिति रहती थी। मगर, नए कानूनों का एक अच्छा पहलू यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर सकेगा। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अब इसका अधिकार होगा। इससे जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा, उसे तुरंत मदद मिल पाएगी। यही नहीं, पुलिस को गिरफ्तारी का विवरण थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इससे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वाले और दोस्त-रिश्तेदार आसानी से सूचना पा सकेंगे। पहले परिवार वालों को कई बार पता ही नहीं चल पाता था।

बस्ती (जीकेबी)। पहली जुलाई से नया कानून लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों से लेकर अधिवक्ता तक धाराओं को लेकर भ्रम में उलझे हैं। पीड़ित भी थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद आश्वस्त नहीं है कि उसकी तहरीर के हिसाब से धाराएं लगाई गईं या नहीं। इसके लिए वह अधिवक्ता से संपर्क करने में वक्त जाया कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को भी अभी धाराएं याद नहीं हो पाई हैं। लिहाजा उन्हें भी नए कानून की किताब पलटनी पड़ रही है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि थाने के मुंशी दीवान से लेकर विवेचकों तक को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मगर, उनकी लगाई धाराएं माकूल हैं कि नहीं इसका पता बिना कानून की किताब पलटे समझ में नहीं आ रहा है।

आईजी आरके भारद्वाज ने बताया कि धीरे-धीरे सभी अभ्यस्त हो जाएंगे। अभी नए कानून की धाराएं याद नहीं हो पाई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को भी नए कानून के बारे में जागरूक किया जा सके। नए कानून लागू होने के बाद किसी भी आपराधिक मामले में मुकदमे की पहली सुनवाई के 90 दिनों के अंदर ही आरोप तय कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे और 90 दिन ही जांच हो सकेगी। आरोपी को आरोप मुक्त होने का निवेदन 60 दिनों में ही करना होगा। खास बात यह है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए धारा 63-99 तक तय की गई हैं। दुष्कर्म को धारा-63 से परिभाषित किया जाएगा। इसकी सजा के बारे में धारा 64 में बताया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा-70 और यौन शोषण का अपराध धारा 74 में परिभाषित है। दहेज हत्या की धारा-79 और दहेज प्रताड़ना की धारा-84 है।

सोनौली कस्बे में कई अवैध पार्किंग जबरन बैठाते हैं सवारी

महाराजगंज (जीकेबी)। नेपाल बॉर्डर के करीब सोनौली कस्बे में कई अवैध पार्किंग बने हैं। यहां देश के महानगरों के लिए सीधी बस सेवा मिलती है। नेपाल से आने वाले पर्यटकों को गुमराह कर बसों में जबरन बैठा लिया जाता है। इससे परिवहन निगम को लाखों का चूना लग रहा है। दूसरी ओर धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता से इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

जानकारी के अनुसार, नेपाल से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जयपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी, नोएडा समेत अन्य शहरों में लोग जाते हैं। सोनौली डिपो की ओर से भी इन शहरों के लिए बस सेवा है, लेकिन सोनौली कस्बे में तमाम अवैध पार्किंग बन गए हैं। सूत्रों की माने तो खाली पड़ी निजी जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ रही है। सोनौली बस स्टेशन से एक डेढ़ किमी के दायरे में कई अवैध पार्किंग बन गए हैं। इसी में दूर-दराज से आने वाली बसें खड़ी होती हैं। इनमें सवारी लाने के लिए पूरा नेटवर्क काम करता है।

पोस्टर-बैनर लगाकर करते हैं प्रचार

सूत्रों की माने तो कुछ बिचौलिए अन्य जिलों व प्रदेश की बसों को लाकर सोनौली बस स्टैंड में खड़ा करते हैं। पोस्टर बैनर लगाकर जगह-जगह प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। 25 जून को उक्त अवैध बस स्टैंड से टूर परमिट की प्राइवेट बस को सवारी भरने के आरोप में एआरटीओ ने सीज किया था। इसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

धंधेबाजों की नजर नेपाल से आने वाले लोगों पर होती है। बस में सस्ता किराया व बेहतर सुविधा का झांसा देकर बस में बैठाकर मनमाना किराया वसूल करते हैं। बस में सवार यात्री परेशान होते हैं, लेकिन कहीं शिकायत नहीं कर पातें हैं। दूसरी ओर सोनौली डिपो को नुकसान हो रहा है। सरकारी बस में यात्री कम मिलते हैं, प्राइवेट वाले मोटा रकम कमाते हैं। रोडवेज बस अड्डे से एक किलोमीटर परिधि के अंदर कोई प्राइवेट बस अड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है।

प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शासन ने सड़क पर सवारी भरने व डग्गामारी रोकने के निर्देश हैं। इसके बाद भी सोनौली प्राइवेट बस स्टैंड से दर्जनों की संख्या में डग्गामार बसों में दिल्ली, आगरा सहित अन्य जगहों के लिए मनमानी तरीके से सवारियां भरी जाती हैं। सोनौली रोडवेज बस डिपो से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दर्जनों की संख्या में अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर नेपाल से आने वाली सवारियों को अपने बसों में बैठा कर दिल्ली पहुंचाते हैं।

सवालों के घेरे में वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था

वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

महराजगंज( )। सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग में तेंदुओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों 15 दिनों के अंदर दो तेंदुओं की मौत किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है।

दोनों की मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। वन क्षेत्र के अंदर वन्य जीवों के लिए भोजन समेत अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए संसाधन कितने हैं इस पर जिम्मेदार गंभीर नहीं हैं।

सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग बिहार और नेपाल सीमा से लगा हुआ है। वन क्षेत्र में वन्य-जीवों की सुरक्षा के नाम पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। इनकी सुरक्षा और संरक्षण के नाम पर महज कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इसकी हकीकत बीते 15 दिनों के अंदर जंगल में दो तेंदुए का शव मिलने के बाद सामने आई है। मौत को जिम्मेदार भले ही बीमारी बता रहे हों, लेकिन इससे साफ है कि जिम्मेदारों की लापरवाही से वन्य जीवों को खतरा बना हुआ है।

इतना ही नहीं वन विभाग के जिम्मेदार बीमारी बताने के अलावा कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा को लेकर सजग रहने वाले लोगों ने नाम ने उजागर करने की शर्त पर बताया कि तेंदुए की मौत कोई छोटी बात नहीं है। बल्कि यह गंभीर विषय है कि जंगल में आखिरकार उनकी मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है। इसकी गहनता से जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार तेंदुए का शव कई दिनों तक जंगल में पड़ा भी रहा तो उस पर वन विभाग के सुरक्षा प्रहरी की नजर क्यों नहीं पड़ी? वन्य सेंचुरी एरिया में तेंदुए की मौत का होना कोई मामूली बात नहीं है। वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता इससे जरा भी सहमत नहीं हैं कि लगातार बीमारी से तेंदुए की मौत हो रही है।सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग नेपाल के चितवन और बिहार राज्य के सरहद से लगा हुआ है। इसके नाते यहां पर वन्य जीवों की चहलकदमी होती रहती है। जंगलों में लगने वाली आग, शिकारियों और वन माफियाओं से वन्य जीवों को खतरा बना रहता है।

मैरुंड घोषित, सुबिका बाबू गांव

बस्ती (जीकेबी)। दुबौलिया क्षेत्र में बंधे से करीब दो किलोमीटर दक्षिण स्थित सुबिका बाबू गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिर गया है। गांव को मैरुंड घोषित करते हुए प्रशासन ने गांव के लोगों के आने जाने के लिए तीन मोटरबोट व पांच नाव लगा दिया है। एडीएम प्रतिपाल चौहान ने मोटरबोट से गांव का भ्रमण कर स्थिति की जानकारी ली। तत्काल नाव की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश दिया। गांव में स्वास्थ्य विभाग व पशु पालन विभाग की टीम भेजी गई है। यह गांव काफी दुर्गम क्षेत्र में है,प्रत्येक वर्ष यह गांव मैरुंड हो जाता है। इस गांव की आबादी करीब तीन सौ है।

पहली बारिश : अयोध्या पानी-पानी

अयोध्या को विश्वस्तरीय नगरी बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मुखिया ने संकल्प किया है। इसके लिए उन्होंने राजकोष के दरवाजे पूरी तौर पर खोल दिए कि अयोध्या के लिए धन की कोई कमी नहीं होने पायेगी। लेकिन जिस प्रकार पहली ही बरसात में पूरे शहर की सांसत हुई है, उससे बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ इंजीनियरों को निलम्बित कर दिया गया है जो जल्द ही बहाल भी हो जायेंगे। 35 हजार करोड़ कम तो नहीं होते हैं, जिससे अयोध्या को भव्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। केन्द्र की योजनाएं तो इससे अलग हैं। फिर भी गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुए हैं इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। पानी भरने से सड़कों में हुए गड्ढ़ों को पाटने के लिए अब ट्रालियों में गिट्टी भर कर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया है जैसे ही सड़क टूटे गिट्टी डाल दी जाये। अयोध्या की नवनिर्मित चौड़ी हुई सड़कों ने लोगों के घर दुकानें तोड़-फोड़ कराकर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सौन्दर्यीकरण भी कर दिया लेकिन पहली बरसात में सारे दावों की पोल खुल गई और जब-जब पानी बरस रहा है तब-तब स्थितियां विद्रूप हों जा रही हैं। पहली बारिश में जिस प्रकार पूरी अयोध्या पानी-पानी हो गई वह दुनिया भर के लिए एक खबर बन गई। जितना प्रचार दिसम्बर से फरवरी तक हुआ था वह बरसात के एक ही पानी में धुल गया।

अयोध्या के एक इलाके में जलभराव को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव (जो कांवड़ यात्रा की समीक्षा करने अयोध्या आये थे) ने मौके पर जाकर स्थिति देखी तो फटकार लगायी कि आखिर यह पानी सीवर में क्यों नहीं जा रहा है। जिस प्रकार नई सड़कों के टूटने और धंसने तथा जलभराव से अयोध्या के लोग परेशान हैं। उससे तो यही लगता है कि सड़कों का निर्माण तकनीकी दोषपूर्ण है, भ्रष्टाचार उसका कारण है या बरसात ही दोषी है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार अयोध्या में पानी बरसा हो । जलभराव सीमित होता था। जनौरा जैसे इलाके जरूर डूब क्षेत्र बन जाते थे जहां इतना पानी भर जाता था कि निवासियों को पहली मंजिल पर रहना पड़ता था । 3 बढ़ती आबादी, जहां-तहां मकानों का बनना, उसके लिए जलनिकासी की व्यवस्था न होना एक बड़ा कारण है। नालों और नालियों की स्थिति भी ऐसी है कि वहां प्रवाह हो ही नहीं पाता है ऐसे में जल भराव होना ही है।

कहने को कहा जा सकता है कि पूरा आवां का आवा ही गड़बड़ा गया है। जिसके दुष्परिणाम जगह-जगह दिख ड़ रहे हैं। जो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। यदि पानी की टंकी भरभरा कर गिरने से कई लोगों को मौत हो जाती है तो यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। क्या पिछले कई वर्षो में निर्माण की गुणवत्ता से बहुत समझौते किए गए या उसमें लगाई गई निर्माण सामग्री दोयम दर्जे की थी। काम हुआ, पैसा मिला, फिर लोग आगे बढ़ गए उसका भविष्य क्या होगा इसके बारे में सोचने की किसे फुर्सत है। सरकारी निर्माण में नाली और खडण्जे तक के लिए तरह-तरह की शिकायतें आती हैं कि कहीं ईंटा पीला लग रहा है तो कहीं सीमेंट दोयम दर्जे की इस्तेमाल हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ शिकायतें ही हैं। गांव से लेकर शहर तक बंदरबाट का नतीजा है कि विकास की जो गंगा बह रही है उसमें सभी नहाने धोने में लगे हैं। जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तब तक सब निपट चुका होता है।'

निर्माण में ठेकों की एक लम्बी प्रक्रिया होती है। जिसमें बड़े ठेकेदारों से लेकर छोटे ठेकेदारों तक से काम कराये जाते हैं। निचले स्तर पर काम करने वाले मजदूर होते हैं काम तो वहीं करते है। ऐसे में निगरानी का कार्य सरकारी तंत्र का रहता है कि जिस मानक के अनुरूप कार्य कराया जाना था वह मानक के अनुसार हुआ है या है नहीं? मानक के अनुरूप निर्माण न होने और खामियों के लिए कोई तो अपनी जिम्मेदारी लेगा? यदि निर्माण पूरा कराने का प्रशस्ति पत्र ले सकते हैं तो उसके बाद की स्थितियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्य सचिव प्रशासन का मुखिया होता है उसके देखने के बाद भी यदि हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर यह कैसा विकास होगा? जिसके गीत गाते हुए लोग नहीं अघा रहे थे।

विकास के इन पैमानों को देखते हुए यही लगता कि लापरवाही, तकनीकी खामियां और भ्रष्टाचार सभी मिलकर विकास का सत्यानाश कर रहे हैं। नगरपालिका से लेकर नगर निगम बनाने और विकास प्राधिकरणों की सीमा बढ़ा देने से वहां रहने वालों को कितनी सुविधाएं मिली हैं और शहरों का कितना मानक के अनुरूप विकास हो पाया है इसे भी तो कभी देख लेना चाहिए।

समाज और सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित रहीं लक्ष्मीबाई केलकर

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की सफलता में उस भावना की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसने समाज में स्वत्व का बोध कराया । यदि हम केवल आधुनिक संघर्ष का ही स्मरण करें तो हम पाएंगे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ केशव हेडगेवार तक ऐसी असंख्य हुतात्मा हुई हैं जिन्होंने दोहरा संघर्ष किया । एक तो स्वयं सीधा संघर्ष किया और संघर्ष के लिए स्वाधीनता सेनानी भी तैयार किए और दुसरा समाज में स्वत्व और सास्कृतिक जागरण का अभियान चलाया । लक्ष्मी बाई केलकर ऐसी ही एक महाविभूति थीं, जिनका पूरा जीवन भारत राष्ट्र, समाज और सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित रहा ।

लक्ष्मी बाई केलकर का जन्म 06 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ था । उनके पिता दातेजी लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। इस नाते परिवार में राष्ट्र और सास्कृतिक जागरण का वातावरण था । लक्ष्मीबाई इसी के बीच बडी हुई । उनके बचपन का नाम कमल दाते था लेकिन विवाह के बाद वे लक्ष्मीबाई केलकर बनी और वर्धा आ गई ।उनका विवाह चौदह वर्ष की आयु में विदर्भ के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता पुरुषोत्तम राव केलकर से हुआ था ।पुरुषोत्तम जी विधुर थे यह उनका दूसरा विवाह था। दोनों की आयु में अंतर भी था, लक्ष्मीबाई की आयु भले अभी कम थी पर वे मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो रहीं थीं । विवाह के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा भी जारी रखी और पति के साथ समाजसेवा के कार्यों में भी सहभागी बनी ।

यह वह कालखंड था जब स्वाधीनता के लिए अहिसंक आदोलन पूरे देश में प्रभावी हो रहा था । यह संयोग ही था कि लक्ष्मी बाई के मायके का दाते परिवार और ससुराल के केलकर परिवार दोनों इन गतिविधियों में बढ़-बढ़ कर हिस्सा ले रहें थे। पूरा विदर्भ मानो इन अभियानों का हिस्सा था । यही कारण था कि 1923 के झंडा सत्याग्रह का सर्वाधिक पभात पूणे से लेकर विदर्भ तक रहा ।यह इस आंदोलन की त्यापकता का ही प्रभाव था कि आगे चलकर गांधी जी ने नागपर के समीप वर्धा को अपना एक प्रमुख केन्द्र बनाया। अचिवक्ता पुरुषोत्म राव केलकर अपनी पत्नी लक्ष्मी वाई के साथ इन सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते ।

गांधी जी और तत्कालीन आदोलनों का कितना प्रभाव इस परिवार पर था इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता हैं कि लक्ष्मी बाई ने अपने घर में एक चरखा केन्द्र स्थापित कर लिया था । वे सामाजिक जागरण के लिए तीन काम करती थीं। एक तो महिलाओं में चरखे के माध्यम से स्वदेशी और अत्मनिर्भरता की प्रेरणा देतीं, दूसरा भारतीय वाड्मय के उदाहरणों से सामाजिक समरसता का वातावरण बनातीं थी। इसके लिए उन्होंने अपने घर में अनुसूचित समाज के बधुओ को सहयोगी के रूप जोड़ा हुआ था और तीसरा रामचरामचरितमानस के प्रवचन से सास्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों की स्थापना ।वे मानती थी कि राष्ट्र की स्वायत्ता ही सर्वोपरि है । एक बार जब गाधी जी ने एक सभा में दान का आह्वान किया तो उसी क्षण लक्ष्मीबाई ने अपने गले से सोने की चंन उतारकर गांधी जी को समर्पित कर दी थी ।

उनका वैवाहिक जीवन आवक न चल सका । वे अभी मात्र 27 वर्ष की थीं कि 1932 में पति का देहान्त हो गया ।उनके पास दोहरा दायित्व आ गया । परिवार में एक विधवा ननद भी रहतीं थीं । लक्ष्मी बाई ने अपने बच्चों के साथ उन्हें भी सहेजा । लक्ष्मीबाई ने अपनी आवश्यकताए सीमित की पर न बच्चों का शिक्षण रोका न अपनी सामाजिक गतिविधियां कम की। उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा किराये पर उठाया इससे भी कुछ लाभ हुआ । अपनी सामाजिक सक्रियता के चलतें वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के संपर्क में आई । उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग हिस्सा लिया कितु डॉ. हेडगेवार की सलाह पर जेल नहीं गई और बाहर रहकर सामाजिक जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए टोली तैयार करने का काम जारी रखा जो पति की मृत्यु के बाद और तेज हुआ । उनके द्वारा तैयार टोलियों ने विदर्भ में चलने वाले हर आंदोलन में हिस्सा लिया । महिलाएं कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी, निकालती चरखा और खादी का संदेश देती थीं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की सलाह पर वर्धा में 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति नामक संगठन की नींव रखी । इसके लिए भारत भर की यात्रा की और संगठन के कार्य को विस्तार दिया । 1945 में राष्ट्र सेविका समिति का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ।यह वह समय था जब देश के विभाजन वादी शक्तियां प्रबल हो रही थीं । अग्रेजी सरकार का उन्हें सरक्षण था इस नाते उनकी हिंसक गतिविधियां बढ़ गई थीं । विशेषकर बंगाल पंजाब और सिंध में हिन्दू समाज की महिलाओं में एक भय का वातावरण बनने लगा था लक्ष्मी वाई केलकर ने अपने संगठन के माध्यम में महिलाओं में संगठित रहने और आत्मविश्वास जगाने का अभियान चलाया देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय वे सिंध में थी । उन्होंने हिन्दू परिवारों को भारतीय सीमा में सुरक्षित पहुचाने के प्रबन्ध किए।

पेपर लीक कैसे हो जाता हर बार

पेपर लीक कोई है करता
खामियाजा कोई है भरता
गरीब को तो मार दिया तूने
अमीर फिर भी नहीं है डरता
हमारे तंत्र की रग रग में है भ्रष्टाचार
गरीब पर तो हो रहा है अत्याचार
पूरा साल जिसने कुछ नहीं पढ़ा
मेरिट में कैसे आया कुछ तो करी विचार
पेपर लीक की जड़ तक नहीं कोई जाता
संस्थान करोड़ों देकर पेपर को है खरीद लाता
संस्थानों में पढ़ने वाले मेरिट में हैं आ जाते
और गरीब का बच्चा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता
संस्थानों की गर्दन पर जब लटकेगी तलवार
एक ही झटके में सब कुछ आ जायेगा बाहर
पिछले कितने सालों से चल रहा था यह धंधा
यह सब जनता के सामने हो जाएगा उजागर
भ्रष्टाचार मुक्त शाशन बार बार कहती है सरकार
फिर पेपर लीक कैसे हो जाता हर बार
पैसे का जो यह चल रहा है अजब खेल
गरीब आदमी की मेहनत पैसों के आगे जाती है हार

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

मैं भी कभी

दो सौ पेज की छः सामान्य कॉपी चाहिए। भूगोल के लिए एक बड़ी चाहिए; और गणित के लिए एक मोटी। ₹ नीरज ने दुकान वाले युवक से स्टेशनरी के कुछ और सामान निकलवाये। फिर दुकान वाले युवक ने पास में ही खड़े देवीचरण को सात सौ बयासी रूपए का बिल थमाया।

सिर्फ तीन सौ पैंतीस हैं मेरे पास नीरज। एक काम करते हैं बेटा कुछ सामान को रहने देते हैं। बाद में ले लेंगे। कल तुम्हारी फीस भी तो देनी है न चार सौ तीस रूपए। ₹ अपनी जेब की थाह लेते हुए कापियों को उठा-उठा कर देवीचरण देखने लगा।

नीरज बोला- हमारी क्लास में सबने पूरी कॉपी-पुस्तकें खरीद ली है पापा। पढ़ाई भी शुरू हो गयी है। बहुत जरूरी है पापा ये सब।

देवीचरण पल भर खामोश खड़ा रहा। तभी देवीचरण के बगल में खड़े एक अधेड़ शख्स बोले- ₹ ले लो भाई, बच्चा जो लेना चाहता है। जितना आपके पास हैं , आप दे दो। बाकी मैं दे देता हूँ।

भैया ! आप भला क्यों ? मुझे अच्छा नहीं....। देवीचरण के कुछ और कहने से पहले उस शख्स ने कहा- कुछ नहीं भैया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ। मैं ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ। आखिर उस अधेड़ शख्स की बातें देवीचरण ने मान ली। ₹ पिता-पुत्र दोनों सामान लेकर चलने लगे, तभी दुकान वाले युवक ने देवीचरण को चार सौ तीस रुपए थमाते हुए कहा- चाचा जी। इसे रख लो। नीरज की स्कूल की फीस जमा कर देना। वो व्यक्ति जिन्होंने आपको मदद की है, मेरे पापा जी हैं। मैं भी कभी नीरज था चाचा।

टीकेश्वर सिन्हा' गब्दीवाला'
घोटिया बालोद (छत्तीसगढ़)

भारत-रूस रिश्ते पर किसी तीसरे देश की आंच नहीं आने पावे

बैठक से पूर्व की गई कई अन्य घोषणाएं भी भारतीय हितों के अनुकूल रहीं। मसलन, रूस में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का एलान किया गया है। यह जरूरी था, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से रूस से कहीं छोटे देश अमेरिका में हमारे पांच वाणिज्यिक दूतावास हैं, जबकि रूस में अब तक दो ही हैं। बीते करीब तीन दशकों से ऐसा कोई दूतावास रूस में नहीं खुला है, जबकि द्विपक्षीय रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके हैं। नए वाणिज्यिक दूतावास के बाद रूस में हमारी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। कारोबार, पर्यटन आदि से जुड़े कामकाज में इजाफा होगा। वहां के बाजार को समझने में कहीं अधिक आसानी होगी और व्यापार को भी फायदा होगा। इसी तरह, यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से हिस्सा ले रहे भारतीय सैनिकों की वतन वापसी पर बनी सहमति भी काफी अहम है। भारत लगातार यह मांग करता रहा है, जिस पर जल्द ही अमल करने का आश्वासन रूसी राष्ट्रपति ने दिया है।

नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस पहले द्विपक्षीय दौरे पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थीं, जो स्वाभाविक ही था। जब रूस और भारत जैसे बड़े देश मिलते हैं, तो द्विपक्षीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मसलों पर भी बात होती है। विशेषकर यूक्रेन युद्ध को लेकर सबकी उत्सुकता बनी हुई थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रूख फिर से स्पष्ट कर दिया। सुखद है कि भारत-रूस संबंध को लेकर अब पश्चिमी देश किसी मुगालते में नहीं हैं। 2000 के दशक में भी रूस के साथ हमारा काफी अच्छा रिश्ता था, बावजूद इसके अमेरिका ने भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया था। आज भी बेशक पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वर्ष 2023 में भारत ने 46.5 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल रूस से मंगाए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 2.5 अरब डॉलर था।

गत मंगलवार को ऑस्ट्रिया के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस आत्मीय माहौल में बातचीत की मेज पर बैठे, वह इस बात की मुनादी थी कि दोनों देशों के बीच सात दशकों पुराना संबंध अब कितना प्रगाढ़ हो चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर बैठक में आतंकवाद के साथ-साथ यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र छेड़ दिया। उल्लेखनीय है, यूक्रेन संकट के कारण रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है, जिसकी प्रतिक्रिया में मॉस्को भी मुखर है। मगर भारत ने बम बंदूक के बजाय शांति वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। वहीं, आतंकवाद के बहाने रूस को यह एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई कि चीन के साथ उसकी नजदीकी परोक्ष रूप से पाकिस्तान को उत्साहित करती है, जो भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों को खाद-पानी मुहैया कराने का काम करता है। अच्छी बात यह भी रही कि ईंधन के मामले में भारत को स्थिरता प्रदान करने में रूसी योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सराहना की, जो उचित भी था, क्योंकि अब हम खाड़ी देशों के बजाय सबसे अधिक तेल रूस से ही आयात करने लगे हैं।

रूस के साथ ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भी हमारी काफी नजदीकी है। रक्षा संबंध करीब 40 साल पुराना है। हम आज भी जितने रक्षा उत्पाद आयात करते हैं, उसका करीब 60-70 फीसदी हिस्सा रूस से ही आता है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि इन उपकरणों के रख-रखाव, उन्नतिकरण आदि के लिए भी मॉस्को के साथ लगातार संबंधों को मजबूती दी जाए। फिर, जब कभी हमें जरूरत पड़ी है, रूस हमारी मदद के लिए आगे आया है।

इसी तरह, आपसी कारोबार भी दोनों देशों को काफी करीब ला चुका है। हां, भुगतान एक बड़ा मसला जरूर है, जिस पर इस बार अहम बातचीत हुई है। दरअसल, यूक्रेन युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच डॉलर में ही लेन-देन होता था, लेकिन बाद में रूस पर प्रतिबंध और बदली वैश्विक परिस्थितियों के कारण कभी रूबल, तो कभी रुपए, तो कभी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिहरम में व्यापार होने लगा। चूंकि मॉस्को पर लगा प्रतिबंध हाल-फिलहाल में खत्म होता नहीं दिख रहा, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि भुगतान की कोई स्थायी व्यवस्था बने।

ठीक इसी तरह की चुनौती रूसी संसाधनों को लेकर भी है। रूस चूंकि एक विशाल देश है, इसलिए उसके पास प्राकृतिक ऊर्जा, मिनरल आदि के अपार भंडार उपलब्ध हैं। ऐसे में, हमारे लिए यह जरूरी है कि अपने राजनय संबंधों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए हम अपने हितों की पूर्ति करें। अभी वह बेशक पश्चिमी देशों के साथ उलझा हुआ है, लेकिन यह हमारे लिए एक मौका भी है। हमने पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर अपनी मंशा स्पष्ट भी कर दी है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में परोक्ष रूप से चीन पर भी बात हुई। यह स्पष्ट किया गया कि भारत और रूस के रिश्ते पर किसी तीसरे देश, खासतौर से चीन की तरफ से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चीन से हमें सामरिक तौर पर लगातार चुनौती मिलती रही है और वह पाकिस्तान को भी हरसंभव मदद करता रहता है। ऐसे में, मॉस्को से दशकों पुरानी दोस्ती के नाते यह जरूरी था कि हम उसे यह एहसास दिलाएं कि चीन के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, ताकि बतौर मित्र वह हमारी दिक्कतों को समझे और हमारी मदद करे।

वास्तव में, भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के तीन पहलू थे। पहला, रूस के साथ रिश्ते बनाए रखना, साथ ही पश्चिमी देशों को स्पष्ट कर देना कि यह कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत नहीं की जा रही। भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था। दूसरा पहलू है, इस द्विपक्षीय रिश्ते में कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। विज्ञान- प्रौद्योगिकी और 'पीपुल-टु-पीपुल कॉन्टैक्ट' यानी आम लोगों के स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाने पर रजामंदी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। और तीसरा पहलू है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना। भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर इसकी एक बानगी है।

महिलाओं का बार-बार प्रेग्नेंट होना समय से पूर्व बुढापे को निमन्त्रण

प्रेग्नेंसी से महिलाओं में जल्द बुढ़ापा आ सकता है। दरअसल, हर प्रेग्नेंसी के बाद 2 से 3 महीने की बायोलॉजिकल एजिंग बढ़ती है। ऐसे में यदि कोई महिला बार-बार प्रेग्नेंट होती है, तो वह दूसरी महिला की तुलना में जल्द बूढ़ी दिख सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कम उम्र में प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं में एजिंग की समस्या जल्द होती है।

इन महिलाओं में झुर्रियां और झाई, आंखों के नीचे काले घेरे, स्किन की चमक कम होना, चेहरे पर रेड बंप निकलना, स्किन ढीली पड़ना और काले धब्बे पड़ना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, जोड़ों में दर्द, नाखून में दरारें पड़ना, बार-बार सर्दी-खांसी होना, पीरियड्स अनियमित होना, वजन बढ़ना, जीभ पर सफेद परत जमना, क्रैंप, नींद नहीं आना और बाल झड़ना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।

प्रेग्नेंसी का पूरे शरीर पर पड़ता है असर

प्रेग्नेंसी के 9 महीनों में हर महिला का शरीर हर तरह के प्रेशर को झेलता है। इस दौरान महिलाओं में सिर्फ फिजिकल चेंजेज नहीं होता है, बल्कि अंदरूनी अंग भी अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करते हैं। बच्चे के जन्म से पहले महिलाओं के साथ प्रेग्नेंसी के कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। उनका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और हार्ट को बढ़े हुए एक्स्ट्रा ब्लड को पंप करने के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ती है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर का इम्यून सिस्टम बदल जाता है। वहीं इस दौरान ब्लड वॉल्यूम, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि हड्डियों में भी बदलाव आता है।

भ्रूण को मिलता है कैल्शियम

बता दें कि प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भ में पलने वाले बच्चे को मां से बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इस कारण इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्शन बढ़ जाता है। वहीं प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में मां की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं डिलीवरी के बाद बच्चे को मां ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इससे भी बच्चे को बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। दरअसल, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से महिलाओं में बोन डेंसिटी करीब 7 फीसदी तक घटती है। वहीं अगर महिला अलग से भी कैल्शियम का सेवन करती हैं, फिर भी बोन लॉस नहीं रुक पाता है। इसके साथ ही तनाव बढ़ने से भी महिलाएं अपनी उम्र से 8-10 साल बड़ी लगने लगती हैं। कई महिलाएं कम उम्र की होने के बाद भी उम्र में काफी बड़ी दिखती हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रेग्नेंसी है। बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को एंग्जाइटी की समस्या भी होती है। कई महिलाएं डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन्स की मात्रा अधिक होती है। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद अचानक से हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 22 फीसदी से अधिक महिलाएं डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं। डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन कई महीनों तक चलता है। वहीं सही समय पर सही इलाज न मिल पाने पर महिलाएं साइकोटिक डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। यह एक खतरनाक स्टेज मानी जाती है, जिसमें महिला खुद को या फिर अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो कई महिलाएं अपनी उम्र से 4-5 साल तो कुछ 10 साल तक बड़ी दिखती हैं, जिसका मुख्य कारण अधिक तनाव लेना है। जो महिलाएं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या से गुजरती हैं, उनको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

एजिंग की समस्या

बता दें कि आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को गट बैक्टीरिया कहते हैं। जोकि एक वयस्क की आंतों में 100 ट्रिलियन पाए जाते हैं। जिसको माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा भी कहा जाता है। इनमें से 400 से अधिक प्रकार के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, तो आंतों में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया उस खाने को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे खाना आसानी से पचता है और हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं गट बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब गट बैक्टीरिया घटते हैं, तो व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के हार्मोन असंतुलित होते हैं। जिसका असर उनके शरीर के इम्यून सिस्टम पर देखने को मिलता है। वहीं यदि खाना सही से नहीं पचता है, तो इसकी मुख्य वजह आंतों में पाए जाने वाले गट बैक्टीरिया के खत्म होना है। कई बार खाना शरीर को नहीं लगता है। तो बता दें कि बैड बैक्टीरिया सारे न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं। ऐसे में शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स न मिलने पर इसका त्वचा पर बुरा असर पड़ता है।

विवाहित शहीदों के माता -पिता को भी मिले सुविधा

ऐसे में मै रक्षामंत्री से निवेदन करता हूँ कि क्लॉज में बदलाव कीजिये ताकि निराश्रित माता पिता भी दर दर कि ठोकरे खाने से बच सकें।

देश के सपूत शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और शहीद के माता पिता मंजू देवी-रवि प्रताप सिंह के बीच जारी हालिया विवाद को लेकर अब शहीदों के माता पिता कों भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाय। कैप्टन अंशुमान सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए शहीद हो गए। उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान 5 जुलाई 2024 को कैप्टन की पत्नी स्मृति ने लिया। उस वक्त शहीद की मां मंजू देवी भी साथ मौजूद थीं। इसी के कुछ समय बाद शहीद के माता-पिता का बयान आया, जिसमें उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया... उनका कहना है कि सब कुछ बहू लेकर चली गई...उन्हें कुछ नहीं मिला...सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई... उनका बेटा भी चला गया और बहू भी अपने पिता के घर गुरदासपुर जा चुकी है...अब बेटे की तस्वीर के सिवा कुछ भी पास नहीं है। बरडीहा, ज़िला देवरिया, यूपी के मूल निवासी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि वह एनओके के निर्धारित मापदंड में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अवगत करा चुके हैं....उन्होंने कहा कि पिछले साल शहादत से 5 महीने पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी। उसकी कोई संतान भी नहीं है। शहीद के माता-पिता ने दावा किया कि बहू ने अपना एड्रेस भी चेंज करवा लिया है। शहीद के माता-पिता के मुताबिक जो उनके साथ हुआ वो और किसी शहीद के माता-पिता के साथ ना हो। अब कुछ सवाल उठते हैं किसी भी वयस्क को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति को भी है, जैसे शहीद की बेवा को अधिकार है कि पति की मृत्यु के बाद वो दूसरी शादी भी कर सकती है। इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के तहत अनुग्रह राशि देते वक्त ये भी सोचा जाना चाहिए कि शहीद के ऊपर डिपेंडेंट कौन-कौन था। अगर उसके माता-पिता भी जीवित हैं तो उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उनकी तो उम्र भी ऐसी नहीं कि उन्हें कोई नौकरी दे या खुद रोजगार चला सकें। दूसरी ओर शहीद की पत्नी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। वो युवा, पढ़ी लिखी होने के साथ अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकती है। चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। ये सब शहीद के माता-पिता के साथ नहीं हो सकता।

आखिर अपना बेटा खो चुके ये बेसहारे कहा जायेंगे। ऐसे में मै रक्षामंत्री से निवेदन करता हूँ कि क्लॉज में बदलाव कीजिये ताकि निराश्रित माता पिता भी दर दर कि ठोकरे खाने से बच सकें। आज वीर जवान सरहद पर शहीद हो रहें किन्तु इनके शहादत का अपमान होता है। एक शहीद कि शहादत का जो मूल्य है वह मेडल और धन से नहीं चुकाया जा सकता, उसके लिए सम्मान और उसके परिवार का देखभाल मुख्य होना चाहिए।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

राजनीति लाभ एवं सत्ता की संभावनाओं से बेबाक रहे चन्द्रशेखर

अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में चंद्रशेखर ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इंदिरा गाँधी से बातचीत में उन्होंने कहा था 'मैं कांग्रेस को सोशलिस्ट बनाने का प्रयास करूंगा और अगर यह न बन पाए तो इसे तोड़ दूंगा क्योंकि जब तक यह टूटेगी नहीं देश में कोई नई राजनीति नहीं आएगी। चंद्रशेखर आजीवन बेबाक रहे थे। वे राजनीतिक लाभ तथा सत्ता की संभावनाओं की परवाह नहीं करते। विचारधारा एवं राजनीति के संघर्ष में भी उनमें सत्य को कहने, स्वीकारने का साहस है। जेपी के दलविहीन राजनीति के विचार को वह अस्वीकार करते हैं। चंद्रशेखर के अनुसार यह अधिनायकवाद की राह सुगम करती है। कांग्रेस में नेतृत्व चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी का समर्थन करने को उन्होंने ताउम्र अपना सही कदम माना। हालांकि चंद्रशेखर राजनीतिक वंशवाद के विरुद्ध थे। एक विदेशी विद्वान द्वारा आजादी के इतने वर्षों बाद भी व्याप्त भयंकर गरीबी के सवाल पर उन्होंने कहा था, 'मानव इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने बिना गरीबी का अनुभव किए गरीबी मिटाने का प्रयास किया हो।' यह विरासत में मिली सत्ता पर काबिज नेतृत्व के लिए उनके मन का आक्रोश था। चंद्रशेखर मानते हैं कि केवल इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण के कारण भी देश इमरजेंसी की तरफ धकेला गया। चंद्रशेखर शाह आयोग के गठन को जनता सरकार की गलती मानते हैं। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए था क्योंकि चुनावी हार उनके लिए एक बड़ा सबक थी। चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। इंदिरा गांधी की मकान और सुरक्षा जैसी सुविधाएं छीनने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए चंद्रशेखर उन्हें वे सारी सुविधाएं वापस दिलवाई। जनता पार्टी के उस भानुमति की कुनबे को संभालने की जिम्मेदारी अध्यक्षीय रूप में चंद्रशेखर ने ही उठाई।

चंद्रशेखर मानते हैं कि लोकतंत्र वापसी के सीमित उद्देश्य से ही जनता पार्टी का गठन हुआ था और वैचारिक विभिन्नता के कारण उसका विघटन हुआ। चंद्रशेखर ने कभी भी अनर्गल आक्षेप बर्दाश्त नहीं किये तथा ऐसी किसी भी परिस्थिति में सदैव कड़ा प्रतिउत्तर दिया। चाहे डॉ. लोहिया के बलिया प्रवास के दौरान उनके आरोप हों या जेपी के लिए आयोजित चाय पार्टी पर सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा बुलंदशहर के कलकत्ती नरौरा कांग्रेस कैम्प में उनपर धोखे से नेताओं को बुलाने का दोषारोपण हो। लोहिया को उन्होंने कहा था, 'केवल आप ही ईमानदारी के पुतले नहीं हैं। जरा औरों की भी इज्जत रखिए।' ऐसे ही सिद्धार्थ रे को

चंद्रशेखर होना यानि सैद्धांतिक, वैचारिक, तर्क एवं चिंतनशीलता का उच्चतम श्रेणी का व्यक्तित्व, चंद्रशेखर होने का अर्थ ही है, समाजवाद का जीवंत प्रतीक एवं आजीवन लोकतान्त्रिक संघर्ष का नायक होना, इसीलिए कहते हैं, 'यूँ ही कोई चंद्रशेखर - नहीं होता।'

फटकारते हुए उन्होंने कहा था, की 'मुझमें और बहुत सारी कमी हो सकती है पर साहस की कमी नहीं है। और इस नमें देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अपने घर बुलाने के लिए मैं झूठ का सहारा बार लूं।' उनके इसी व्यक्तित्व के प्रशंसक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्र ने कांग्रेस म कार्य समिति की बैठक में पीसी सेठी से कहा था, 'सेठी चंद्रशेखर को डराने की कोशिश मत करना। जब इसको देखता हूं तो कबीर का दोहा याद आता है- 'चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जा को कछु न चाहिए, वह शाहन को शाह।' ऐसे ही थे राजनीति के ऐसे निर्भीक सन्त चंद्रशेखर, जो कभी गलत के समक्ष नहीं झुके। वे अकेले कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे जो आपातकाल विरोध में जेल में निरुद्ध किये गये। चंद-शेखर उस संतत्व के प्रतीक हैं जो वर्तमान भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत विरोध, बदले या कुंठा की राजनीति नहीं की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवाद के नायक चंद्रशेखर मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। वे प्रतीक हैं भारत की मिट्टी से उमड़ी राष्ट्रीय संवेदना की, ग्रामीण समाज के आतंरिक द्वन्द एवं उसकी राजनीतिक चेतना का वे प्रतीक हैं 2 प्राचीन भारत के राजर्षि परंपरा एवं लोकतंत्र के प्रति आम भारतीय के अटूट निष्ठा का। इसलिए चंद्रशेखर होना सहज नहीं है।

17 अप्रैल, 1927 में जन्मे चंद्रशेखर, सदानंद सि-ांह एवं दुरपाती देवी के सुपुत्र थे। उनका पैतृक गांव इब्राहिम पट्टी (बलिया) है। एक बहुजातीय एवं अल्पसंख्यकों की सहभागिता वाले गांव में पले-बढ़े चंद्रशेखर समरसता भरे विचारशील युवा के. रूप में उभरे। 15 अगस्त, 1947 को आजादी के जश्न - जुलुस में शामिल भूखे चंद्रशेखर ने उस संकेत को महसूस किया कि यह आजादी क्या लेकर आने वाली है।

चंद्रशेखर कहते हैं, 'मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक ही काम हुआ है- 'गुलिस्तां में कलियाँ तरसती रहीं, समंदर में बरसात होती रही।' चंद्रशेखर आचार्य नरेंद्र देव की प्रेरणा से राजनीति में आए थे। शोध की ओर आकृष्ट चंद्रशेखर से नरेंद्र देव ने कहा था, 'चंद-शेखर छोड़िए शोध कार्य, देश बनाने के लिए निकलिए।' इलाहबाद विश्वविद्यालय में स्नात्तकोत्तर में दाखिले के साथ 1951 में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होकर समाजवाद के लिए काम करने का निर्धारित उनका ध्येय जीवन भर बना रहा.. यही वे दिन थे जब उन्होंने एक नये समाज के निर्माण का सपना देखा। चंद्रशेखर का कहना था, 'जो आदमी राजनीति में सही ढंग से सोचता है, उसकी प्राथमिकताएं नहीं बदलतीं।' चंद्रशेखर की भी नहीं बदलीं, वे जीवन भर गरीबी, असमानता एवं अभाव के विरुद्ध संघर्षरत रहे। चंद्रशेखर स्मरण करते थे, ₹जब उनके पैर में हुए फोड़े का इलाज नाई के छुरे को गर्म करके किया गया, उनकी मां डाक्टरी सहायता के बिना हैजा से चल बसी। ऐसे अनुभवों ने ही उन्हें प्रेरित किया, 'ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां मानव इन विवशताओं से मुक्ति पा सके.' उनके भीतर शोषण के विरुद्ध, विषमता के विरुद्ध स्वाभाविक आक्रोश और समता के लिए गहरा लगाव था।

आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफेरायबरेली से चुनाव लड़ने का उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

राजनारायण के साथ पार्टी और सदन में होने वाले बहस और झगड़े के बावजूद भी उनके प्रति सार्वजनिक जीवन में चंद्रशेखर का स्नेह हमेशा बना रहा. चंद्रशेखर मानते थे कि राजनारायण के अंतर्मन में उनके प्रति ममत्व भरा है। चंद्रशेखर का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण है। उन्होंने केवल विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति नहीं की बल्कि कई बार अपने वैचारिक प्रतिद्वंदियों के मुक्त हृदय से प्रशंसक भी रहे है। उन्होंने जनता सरकार में जनसंघियों के सहयोगात्मक रवैये की प्रशंसा की। उनका कहना था कि देश को किसी भी आतंरिक संकट की स्थिति से निकालने में संघ मददगार होगा। स्वदेशी के सवाल पर उन्हें संघ के अनुषांगिक संगठनों के साथ भी खड़े होने में कोई समस्या नहीं थी। सदन में चंद्रशेखर का प्रखर व्यक्तित्व 'वन मैन आर्मी' की भांति दीप्तीमान रहा। अटल जी ने कभी कहा था, 'चंद्रशेखर न पक्ष में है न विपक्ष में, वे निष्पक्ष है।' जनवरी, 1983 में उपयुक्त आहार की कमी, पीने के पानी का अभाव, प्राथमिक शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक सद्भाव जैसे पांच मुद्दों पर चंद्रशेखर. ने 6300 किलोमीटर की अपनी भारत यात्रा पर निकल गये। चंद्रशेखर मानते हैं कि भारत यात्रा के पश्चात अपने विपक्षी एकता के साथियों के दबाव में सक्रिय राजनीति में लौटकर उन्होंने गलती की। क्योंकि उसके बाद वह उन बुनियादी मुद्दों पर अधिक काम नहीं कर पाए। चंद्रशेखर कहते हैं, 'कोई व्यक्ति इतिहास का आखिरी व्यक्ति नहीं है. वह सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।' नब्बे में कांग्रेस के बाहरी समर्थन स्वीकारते हुए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा क्यों हुआ? चंद्रशेखर कहते हैं मैं सरकार बनाने की जिम्मेदारी इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसे समय देश की हालत बहुत खराब थी। उस समय सांप्रदायिक और सामाजिक दंगे फसाद चल रहे थे। देश में 70-75 जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था युवक आत्मदाह कर रहे थे। मेरा विश्वास था कि अगर देश के लोगों से सही बात कही जाए तो देश की जनता देश के भविष्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगी। कठिनाइयों के बावजूद मुझे लगा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकता है।' चंद्रशेखर अपने अल्पकालीन प्रधानमंत्रित्व काल में, जैसा कि प्रभाष जोशी कहते हैं, 'आग ही बुझाते रह गये।' वास्तव में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री का पद कर्तव्य पालन की भावना से स्वीकार किया था. लेकिन पद के लिए उन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक 3 गरिमा से समझौता नहीं किया।

कांग्रेस द्वारा पुलिस की जासूसी जैसे क्षुद्र आरोप के जवाब में उन्होंने खम ठोककर इस्तीफा दे दिया। 8 जुलाई, 2007 को राजनीति के कंटकित राहों के इस पथिक का निधन हो गया। उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करना कठिन है। फिर भी कह सकते हैं, चंद्रशेखर होने का तात्पर्य है, धन, पद एवं सत्ता की लालसा से मुक्त होना, चंद्रशेखर होने का मतलब है, वंशवाद-परिवारवाद के लोकतंत्र विरोधी विचार से विरक्ति, चंद्रशेखर होना यानि जातिवाद एवं अवसर-वाद की राजनीति का प्रतिकार, चंद्रशेखर होना अर्थात प्रतिशोध एवं षड़यंत्र की राजनीति से घृणा, चंद्रशेखर होना यानि सैद्धांतिक, वैचारिक, तर्क एवं चिंतनशीलता का उच्चतम श्रेणी का व्यक्तित्व, चंद्रशेखर होने का अर्थ ही है, समाजवाद का जीवंत प्रतीक एवं आजीवन लोकतान्त्रिक संघर्ष का नायक होना, इसीलिए कहते हैं, 'यूँ ही कोई चंद्रशेखर - नहीं होता।'

दिशा सालियान प्रकरण

भाजपा विधायक नितेश राणे से होगी पूछताछ, भेजी नोटिस

दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थीं। वे सुशांत सिंह राजपूत की भी मैनेजर रही थीं। 8 जून 2020 को दिशा के मौत की खबर आई। कथित रूप से दिशा सालियान की मौत एक इमारत की 14 वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस कल 12 जुलाई को भाजपा विधायक नितेश राणे से पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने राणे को दिशा सालियान केस में नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे कल 12 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। दरअसल, राणे ने दावा किया था कि सालियान की हत्या की गई थी।

अपर्णा वस्तारे का फेफड़ों के कैंसर से जूझने के बाद निधन

बेगलुरू (जीकेबी)। कन्नड़ अभिनेत्री, प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का फेफड़ों के कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि दिग्गज कन्नड़ अभिनेत्री, टेलीविजन प्रस्तोता और पूर्व रेडियो जॉकी अपर्णा वस्तारे का गुरुवार रात निधन हो गया। उनके पति नागराज वस्तारे ने बताया कि 57 वर्षीय कन्नड़ अभिनेत्री पिछले दो सालों से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही थीं। डीडी चंदना पर प्रस्तोता के रूप में अपने काम और कई सरकारी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की एंकरिंग के लिए जानी जाने वाली अपर्णा वस्तारे के पास कन्नड़ में अपनी बेहतरीन भाषा-शैली के कारण एक मजबूत प्रशंसक आधार था। 1998 में, उन्होंने दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में लगातार आठ घंटे तक शो प्रस्तुत करके एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1984 में पुट्टन्ना कनागल की आखिरी फिल्म 'मसनदा हूवु' के साथ सिनेमा में अपनी शुरूआत की और कई कन्नड़ टीवी शो में अभिनय किया। वस्तारे बेंगलुरु मेट्रो की घोषणाओं के पीछे की आवाज भी थीं। वह कन्नड़ रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में नजर आईं और लोकप्रिय कॉमेडी शो 'माजा टॉकीज' में 'वरालक्ष्मी' के रूप में उनकी भूमिका को लोगों ने खूब सराहा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई फिल्म, टेलीविजन, साहित्यिक और राजनीतिक हस्तियों ने वस्तारे के निधन पर शोक जताया। सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा, अभिनेत्री और प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता अपर्णा के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। एक बहुमुखी प्रतिभा जो राज्य में घर-घर में मशहूर थी, प्रमुख कन्नड़ चैनलों और सरकारी समारोहों के कार्यक्रमों में कन्नड़ भाषा में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति देकर, हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई।

....जब माधुरी दीक्षित ने इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के लिए अपने प्यार का इजहार किया

बॉलीवुड का क्रिकेट से जुड़ाव बहुत पुराना है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र के कई बड़े नाम एक-दूसरे से जुड़े हैं, जिनमें से कुछ सफल विवाह भी हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक की एक लीडिंग लेडी ने एक बार भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटरों में से एक के लिए अपने प्यार का इजहार किया था? हम बात कर रहे हैं धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित की, जो कथित तौर पर सुनील गावस्कर से प्यार करती थीं। उन्होंने 1992 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह पूर्व बल्लेबाज के लिए 'पागल' थीं। उन्होंने कहा था, मैं सुनील गावस्कर के लिए पागल हूँ। वह बहुत सेक्सी हैं। मैं उनके पीछे भागना चाहती हूँ और वह मेरे सपनों में भी आए थे।₹ इंटरव्यू के समय वह 25 साल की थीं, जबकि क्रि-केटर 43 साल के थे। सुनील गावस्कर को भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे, जिसने कपिल देव की कप्तानी में देश को अपना पहला विश्व कप दिलाया था। माधुरी दीक्षित को आखिरी बार सुनील शेट्टी के साथ लोकप्रिय डांस शो डांस दीवाने सीजन 4 में जज के तौर पर देखा गया था। वह 2018 में इसके प्रीमियर के बाद से ही शो का हिस्सा रही हैं और पिछले तीन सीजन को जज कर चुकी हैं। माधुरी को आखिरी बार नेटफ्लिक्स शो द फेम गेम वेब सीरीज में देखा गया था, जिसका प्रीमियर फरवरी 2022 में हुआ था। इस शो का निर्देशन बेजॉय नांबियार और करिश्मा कोहली ने किया है, जबकि इसके निमार्ता श्री राव हैं। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, मानव कौल, लक्षवीर सरन और मुस्कान जाफरी हैं। इस शो का निर्माण करण जौहर, श्री राव और सोमेन मिश्रा ने धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है। उनकी आखिरी सिल्वर स्क्रीन रिलीज माजा मा है, जो 2022 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, गजराज राव, ऋत्विक भौमिक, बरखा सिंह, सृष्टि श्रीवास्तव और सिमोन सिंह मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्माण लियो मीडिया कलेक्टिव के बैनर तले अमृतपाल सिंह बिंद्रा ने किया है।

ज्यादातर बाबाओं की पृष्ठभूमि भी गरीब तबके की

इस देश में लोगों की हालत की दारुण हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2001 में जयराम दास उर्फ रामजी बाबा को पुलिस ने अपनी एक शिष्या सुधा शर्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से पता चला कि बाबा अपने दरबार में आने वाली खासतौर से निःसंतान औरतों को संतान के नाम पर दुष्कर्म करता था। इस बाबा ने सैकड़ों औरतों से दुष्कर्म किया। बाबा के झांसे का शिकार हुई ज्यादातर औरतें ओबीसी वर्ग से थीं।

पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने और घरेलू समस्याओं से जूझती अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी औरतों को गिरफ्तारी के बाद बाबा के कांडों की जानकारी मिल गयी। इसके बावजू दअस्पताल में भर्ती बाबा से मिलने के लिए ऐसी औरतों का मेला लग गया। यह स्थिति बताती है कि जागरूकता और आधुनिक तो दूर, सामान्य सुविधाएं भी आम लोगों से काफी दूर हैं। ऐसी ही हालत का फायदा देश के दूसरे बाबा भी उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शासन-प्रणाली को इनकी गैर कानूनी हरकतों और भक्ति की आड़ में लोगों से अपना उल्लू सीधा करने की जानकारी नहीं होती। ज्यादातर मामलों में नेता और अफसर ही इन बाबाओं के समक्ष हाथ जोड़े खड़े होते हैं। ऐसे में किसी की क्या मजाल फर्जीवाड़े और अपराधों की जानकारी होने के बावजूद बाबाओं का कोई कुछ बिगाड़ सके। बाबाओं के पिछलग्गू भक्तों के रेले से सारे नेता सहमे रहते हैं। डर वोट बैंक का होता है। अफसर ऐसे बाबाओं की आपराधिक कुंडली मौजूद होने के बावजूद काररावाई करने से कतराते हैं। उन्हें नेताओं का डर लगा रहता है और नेताओं को बाबाओं का क्योंकि बाबाओं के पास भक्तों के हुजूम के तौर पर उन्हें वोट बैंक नजर आता है।

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख **गुरमीत राम रहीम** हाल में हत्या के मामले में सजा पाए हैं। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने। वह खुद को रॉकस्टार बाबा के यप में प्रस्तुत करते रहे। इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया है पत्रकार और सेवादार की हत्या के आरोप में गुरमीत जेल में हैं। वास्तविकता तो यह है कि बिग बॉस में अपनी बेहूदा हरकतों के चलते ओम बाबा सुर्खियों में आए। टाडा आर्म्स अधिनियम प्रकरण के चलते **ओम जी स्वामी** पांच साल जेल में सजा काट चुके हैं। साल 1972 में उन्होने साधु का रूप धारण किया। इन पर चोरी, ठगी जैसे आरोप हैं।

टीवी चैनलों पर चर्चित **निर्मल बाबा** काफी लोकप्रिय थे। ये ऊटपटांग उपाय बताकर लोगों की समस्याएं सुलझाने का दावा करते थे। निम्रल बाबा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले दर्ज हैं। निर्मल बाबा कहते हैं कि उनकी संस्था के बैंक खाते में पैसे जमा कराने से दुःख दूर होते हैं।

मूलरूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले **असीमानंद** का **असली नाम नव कुमार** है। वह 1990 से 2007 के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत प्रचारक प्रमुख रहे अजमेर दररगाह में 2007 में हुए विस्फोट मामले में आरोपी रहे हैं। देश में गरीबी, बेरोजगारी होने और सार्वजनिक सुविधाओं एवं पर्यापत शिक्षा का अभाव ऐसे फर्जी बाबाओं की दुकान चलाने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। सरकारों के पास लोगों की इन समस्याओं का इलाज नहीं है। ऐसे में बाबा बरगला कर लोगों से अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। इनमें भी खास बात यह है कि भगदड़ जेसे हादसों में करने वाले ज्यादातर गरीब और वंचित तबके के लोग होते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा के पास जादू की छड़ी है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके विपरीत बाबा न सिर्फ धार्मिक आस्था के नाम पर न सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि गैर-कानूनी धंधों में भी लिप्त हैं। शासन और प्रशासन पर इनके भारी रसूख का प्रभाव होने के चलते इनक खिलाफ कारखाइ नहीं होती, जब तक पानी सिर से न गुजर जाए।

बाबाओं से नाराजगी लेने का मतलब है वोट बैंक को नाराज करना। यही वजह रही हाथरस कांड में 116 लोगों की मौत के बावजूर हरि सरकार उर्फ भोले बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया।

बाबा के सेवादारों के नाम दर्ज किये गये। पुलिस जब तक मजबूर न हो जाय, बाबाओं के कारनामों पर कारखाई करने से कतराती रहती है। ऐसे मामलों की फेहरिस्त लम्बी है, जब अपराधों की जानकारी होने के बावजूद पुलिस के बाबाओं के खिलाफ कारखाई करने में हौसले पस्त हो गये।

आसाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की। धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। साला 2013 से यह नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। इन पर आरोप है कि यह आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करते और बलात्कार करते थे। हालांकि अब तक इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। इसी तरह खुद को देवी बताने वाली **सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां** का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। चार अप्रैल 1965 को पंजाब के जिला गुरदासपुर के दोरंगला गांव में जन्मी सुखविंदर कौर पति की खराब आर्थिक हालत के चलते मुंबई में दूसरों के घरों में काम करती थीं। महज दसवीं तक पढ़ी राधे मां की 17 साल की उम्र में शादी हुई थी। कुछ साल पहले इन्होंने खुद को महंत घोषित कर दिया था। इनपर खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे गम्भीर मामले चल रहे हैं।

हाथरस की घटना बहुत कुछ कहती है, सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही का दमन देश के पिछड़े तबके के लिए कोढ़ में खाज साबित हुआ है। इस हालत ने देश में फर्जी बाबाओं को पनपने का मौका दिया है। ज्यादातर बाबाओं की पृष्ठभूमि भी गरीब तबके की रही है। इसी का फायदा जालसाजी करके बाबाओं ने उठाया है। आम लोगों की दुख तकलीफ जब शासन-प्रशासन से दूर नहीं हो पाती है तब उन्हें लगता है कि चमत्कारिक ढंग से इसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्वयंभू बाबा दैवीय शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त करने का दुष्प्रचार करते रहे हैं।

ऐसे मिथ्या और कपटी प्रचार से बाबा दुखी लोगों को आकर्षित करने में कामयाब हो जाते हैं। पर्याप्त प्रचार के बाद जब भक्तों की संख्या हजारों में हो जाती है, तब बाबाओं की तरफ कोई निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। भक्तों की फौज के दाम पर बाबा हर तरह की गैर कानूनी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com